mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-29 अंक-84 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

28 मार्च 2025 शुक्रवार

दैनिक मीडिया ऑडीटर

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

ऋषभ के बचाव...

@ पेज 7

केंद्रीय मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे पप्पू यादव, ओम बिरला ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज एक बार फिर सदन के भीतर शिष्टाचार का पाठ पठाया है। बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन की मर्यादा की याद दिलाने के एक दिन बाद गुरुवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की क्लास लगाई है। उन्होंने पप्पू यादव को किसी केंद्रीय मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर बात नहीं करने की नसीहत दी। दरअसल, पप्पू यादव, सदन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के बगल में बैठे थे। उन्हें मंत्री के साथ बातचीत करते देखा गया और इस दौरान उन्होंने नायडू के कंधे पर हाथ

रख दिया था। ओम बिरला ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद को मंत्री के कंधे पर हाथ रखने के प्रति आगाह किया। सूत्रों ने बताया कि यादव अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एक हवाई अड्डे के बारे में बातचीत कर रहे थे।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान उस वक्त सभी चौंक गए थे, जब ओम बिरला ने राहुल गांधी को सख्त लहजे में हिदायत दे दी थी। उन्होंने राहुल से सदन के नियमों का पालन करने को कहा। हालांकि, राहुल ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन्हें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा था कि वह नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें। इसके बाद, कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया था कि सदन को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बिरला ने शून्यकाल के बाद कहा था, ''कई पिता-पुत्री, माता-बेटी और पति-पत्नी इस सदन के सदस्य रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करेंगे।'' इस बीच, भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सदन की कार्यवाही का एक वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल गांधी अपनी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के गालों को प्यार से स्पर्श करते देखे जा सकते हैं। यह वीडियो कुछ दिन पहले की कार्यवाही के दौरान का है।

आशा वर्कर्स को बड़ी सौगात, 7000 रुपये अतिरिक्त मासिक भत्ता मिलेगा

केरल (एजेंसी)। केरल में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 46 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कोट्टायम जिले में भाजपा शासित एक स्थानीय निकाय ने सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये का अतिरिक्त मासिक भत्ता देने की घोषणा की। मुथोली ग्राम पंचायत ने आशा कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा पंचायत के 2025-26 के वार्षिक बजट में की गई, जिसे सोमवार को पारित किया गया। राज्य की राजधानी में सचिवालय के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का विरोध हाल ही में अनिश्चितकालीन सामूहिक भूख हड़ताल शुरू होने के साथ तेज हो गया है। पिछले सप्ताह राज्य सरकार

के साथ वार्ता विफल होने के बाद भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया। मुथोली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रंजीतजी मीनाभवन ने कहा, ''इस समय, हमने आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से बजट में 12 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जिससे प्रति कार्यकर्ता सालाना 84,000 रुपये की अतिरिक्त राशि सुनिश्चित होगी।'' पंचायत में 13 आशा कार्यकर्ता हैं, जिनमें से सभी को उनके मौजूदा मानदेय और प्रोत्साहन के अलावा 7,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। आशा कार्यकर्ताओं की मांग और विरोध प्रदर्शन पर वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि, ÷आशा कार्यकर्ताओं की शिकायतें बहुत प्रासंगिक हैं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को उन पर विचार करना चाहिए और उन्हें नियमित वेतन पर रखा जाना चाहिए।÷

रोड पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस के आदेश पर जयंत चौधरी का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। नमाजियों पर मेरठ पुलिस की कारवाई पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कहा गुरुवार को कहा कि ÷मेरा मतलब है कि पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लेंगे। प्रशासन सड़कों को ख़ाली रखने की बात कर सकता है लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करनी चाहिए। दरअसल, मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों और रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। मेरठ पुलिस के इसी आदेश की केंद्रीय मंत्री और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने निंदा की है और

कहा कि पासपोर्ट रद्द करने की बात करना गलत है। बता दें कि मेरठ पुलिस की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सड़कों पर नमाज अदा करने की किसी भी घटना को रोकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही पढ़ी जाए। रोड और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पीएसी और आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) सहित पुलिस और अर्धसैनिक बलों को ईदगाह जैसे प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा और ड्रोन और वीडियो कैमरों सहित अतिरिक्त निगरानी की जाएगी। पुलिस ने बताया कि ईद-उल-फ़ितर के दिन संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। पुलिस ने बताया कि सादे कपड़ों में और स्थानीय खुफिया इकाई (स्क्रू) के अधिकारी भीड़ के साथ घुल-मिलकर आदेशों का उल्लंघन करने की किसी भी योजना का पता लगाएंगे।

पति से नहीं मिले 500 रुपये तो छज्जे पर चढ़ गई महिला, सुसाइड की कोशिश

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, यहां एक महिला महज 500 रुपये की खातिर अपनी जान देने पर उतारू थी, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जैसे-तैसे महिला को नीचे उतारा वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। वह लगातार पुलिस को भी कूदने की धमकी दे रही थी, इसके बाद बड़ी मुश्किल से विशाखापत्तनम पुलिस के एसआई भास्कर ने चालाकी से महिला को बचा लिया। विशाखापत्तनम के पीएम पालम स्थित वाईएसआर कॉलोनी में अचानक हंगामा खड़ा हो गया जब सूरी नाम की एक महिला एक बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़ गई और कूदने की कोशिश करने लगी। लोग उसे बचाने के लिए महिला से बात करने लगे। तो महिला ने बताया कि वह अपने पति से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है।

यूपी पुलिस में आ रही है बड़े पैमाने पर भर्ती, विभिन्न पदों में होगी भर्ती

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में योगी सरकार पुलिस महकमे में जल्द ही 28,138 पदों पर सिपाहियों की भर्ती करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अप्रैल और मई महीने में नई भर्ती प्रकिया शुरू करने का ऐलान किया है। बोर्ड अप्रैल और मई में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। बोर्ड द्वारा इसी वर्ष साठ हजार से अधिक आरक्षियों एवं रेडियो संवर्ग के चौदह सौ से अधिक पदों पर भर्तियां पूरी की हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सरकार के मंशा के अनुरूप आगामी भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर ली है। बोर्ड अप्रैल 2025 के अंतिम सप्ताह या मई 2025 के प्रथम सप्ताह से अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस भर्ती

प्रक्रिया में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) के 4,242 पद, प्लाटून कमांडर (पीएसी) के 135 पद, प्लाटून कमांडर (विशिष्ट बल) के 60 पद और जनपद बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए महिला पीसी के 106 पद शामिल हैं, जिसके तहत कुल 4,543 पदों पर उप निरीक्षक स्तर की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त आरक्षी स्तर पर भी विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया उसी समय शुरू होगी। इसमें आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशिष्ट बल और महिला आरक्षी पीएसी के 15,904 पद, आरक्षी (नागरिक पुलिस) के 3,245 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद और जेल वार्डन के 2,833 पद शामिल हैं। इसके तहत आरक्षी स्तर पर कुल 22,053 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह, कुल 26,596 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी।

मंत्रालय में दो दिवसीय चिकित्सा शिविर का समापन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल में मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय लिवर जांच शिविर का मंगलवार को समापन हो गया। शिविर में कुल 525 लोगों ने जांच करवाई और परामर्श लिया। अंतिम दिन 270 मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जांच करवाई। शिविर में लंबी कतारें देखी गईं। कई कर्मचारियों को बिना जांच कराए वापस लौटना पड़ा। कर्मचारियों ने संघ से शिविर की अवधि बढ़ाने की मांग की। हालांकि, अत्याधुनिक फाइब्रोस्कैन मशीन केवल दो दिन के लिए आवंटित थी। संघ ने अगले महीने पुन: दो दिवसीय शिविर लगाने का आश्वासन दिया है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों - डॉ. अंकित शर्मा, डॉ. रोहित श्रीवास्तव, डॉ. शिवांगी दीक्षित और डॉ. दीप्ति मनोहर हार्डे ने जांच की। दंत चिकित्सक डॉ. संदीप मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएमएचओ भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने शिविर की निरंतर मॉनिटरिंग की। शिविर में 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग का आभा ऐप कर्मचारियों के मोबाइल में डाउनलोड कराया गया, जिसमें उनकी संपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी संग्रहित रहेगी। समापन समारोह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना, एनएचएम एनसीडी उपसंचालक डॉ. आशीष और सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी उपस्थित रहे। मंत्रालय डिस्पेंसरी के कर्मचारियों निशा पवार, रिचा राठौर, विजय चतुर्वेदी और सीमा कोरी ने महत्वपूर्ण आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनएमपीएस का बड़ा प्लान

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल में एनएमपीएस (नई पेंशन योजना के कर्मचारी संगठन) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवाड़ी जिला अध्यक्ष अनिल बाजपेई, भोपाल जिला अध्यक्ष पटेल और एमपीवी विभाग अध्यक्ष भरत मिश्रा सहित अखिलेश तिवारी उपस्थित रहे। बैठक में दो प्रमुख निर्णय लिए गए। पहला, 1 अप्रैल 2025 को काला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। शाम 5 बजे विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। दूसरा, 1 मई 2025 को दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए भोपाल के सभी विभागों से अग्रिम बुकिंग की जाएगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष परमानेंट डेहरिया के निर्देशन में आयोजित किया जाएगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली है, जिसके लिए वे लगातार संघर्षरत हैं।

तीन दिवसीय नि-शुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुँचे मंत्री पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल झिरना रोड नरसिंहपुर स्थित आयुष चिकित्सालय में मणिनागेन्द्र सिंह फाउंडेशन द्वारा लगाये गये निःशुल्क ऑस्टियोपैथी दर्द निवारक चिकित्सा शिविर में शामिल हुए। मंत्री श्री पटेल ने सर्वप्रथम भगवान धनवंतरी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रणाम किया। साथ ही स्व. मणिनागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किये। यहां उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत की। मंत्री श्री पटेल ने शिविर में आये डॉक्टरों से कहा कि आप हर वर्ष आकर अपनी सेवाएं दें और चिकित्सालय के स्टाफ़ को प्रशिक्षित करें।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये एससीईआरटी को सुदृढ़ करें : स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाये। शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से निरंतर अपडेट रखा जाये। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हो रहे नये शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की नामांकन दर को बढ़ाने के लिये समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाये। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह बुधवार को मंत्रालय में नई शिक्षा नीति-2020 की टॉस्क फोर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में टॉस्क फोर्स के सदस्यों ने विभिन्न विषयों से जुड़े सुझाव दिये।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक कार्य से लगे शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का भार कम किया जाये। शिक्षक शालाओं में उपलब्ध संसाधनों का शत-प्रतिशत उपयोग करें, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थियों की नामांकन दर को बढ़ाने के लिये प्राध्यापकों

को जिम्मेदारी दी गयी है। वे उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) देने के बाद उनके पुनः प्रवेश की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग का मैदानी अमला शालावार इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करे। बैठक में विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर योग की शिक्षा देने का भी सुझाव दिया गया। बैठक में बताया गया कि 4473 पूर्व प्राथमिक शालाओं में करीब एक लाख बच्चे दर्ज हैं। इन शालाओं के शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज बच्चों को पीएम पोषण उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। करीब 40 हजार आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। मिशन अंकुर के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग किट और जादुई पिटारा उपलब्ध कराया गया है। कक्षा-1 और 2 के बच्चों और अभिभावकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिये एफएलएन मेला आयोजित किया गया है। इस मेले के माध्यम से छोटे बच्चों के अभिभावकों को बच्चे की क्षमता के बारे में कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है। फ्लोर गेम के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई में रुचि जागृत करने के लिये खेल आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

विद्यार्थियों के लिये ऑनलाइन ट्रेकिंग की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष छात्रवृत्ति, गणवेश, साइकिल की व्यवस्था शैक्षिक सत्र के साथ हो, इसके लिये विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल ने बताया कि प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें अप्रैल माह में ही उपलब्ध करा दी जायेंगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में 3471 हाई स्कूलों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अत्याधुनिक आईसीटी लैब तैयार की गयी है।

हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के 44 हजार शिक्षकों को टेबलेट के लिये राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

धान उपार्जन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिये जांच दल गठित करने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अन्तर जिला/जिले में उपार्जन केन्द्रों से दी गई धान के सत्यापन एवं अन्य शिकायतों की जांच के लिये जांच दल गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने विस्तृत जांच के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर विस्तृत जांच करायें। जांच दल के अध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर होंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक / खाद्य अधिकारी संयोजक होंगे। उप/सहायक आयुक्त सहकारिता/ महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन सदस्य होंगे। जांच दल द्वारा उपार्जित धान, धान परिवहन, धान जमा, धान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलरवार धान प्रदाय की मात्रा, धान उठाव की मात्रा और मिलरवार सीएमआर जमा मात्रा की विस्तृत जांच की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि गोदामों में धान कम मात्रा में जमा होने के कारणों की जांच कराई जायें एवं संबंधित उपार्जन समिति/परिवहनकर्ता आदि से शार्टेज मात्रा की वसूली कर संबंधित किसानों को भुगतान किया जाएं। उपार्जन केन्द्रों पर धान की शार्टेज मात्रा की प्रतिपूर्ति बाजार एवं अन्य माध्यमों से कदापि नहीं कराई जाये। उपार्जन केन्द्रों से धान परिवहन के लिये मिलर्स द्वारा उपयोग किये गये वाहन, परिवहन दिनांक एवं मात्रा की जानकारी सीएसएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे धान परिवहन करने वाले वाहनों का विवरण प्राप्त किया जायें। उपार्जन केन्द्र से उठाई गई धान परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की ट्रेकिंग एवं डाटा जिले से एवं टोल नाकों से प्राप्त करें। जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से धान परिवहन में उपयोग किये गये वाहनों की श्रेणी, प्रकार और लोडिंग क्षमता की जानकारी प्राप्त करें। इन बिन्दुओं पर जांच कर अनियमित्ता पायें जाने पर नियमानुसार तत्काल संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

केन्द्रीय सचिव शमी राव ने उद्योग प्रतिनिधियों और अधिकारियों संग निवेश एवं नीतिगत सुधारों पर की चर्चा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और तेज़ बनाने पर केंद्रित दो उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित हुई। बैठकों में प्रमुख सचिव श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, केन्द्रीय टेक्सटाइल श्रीमती नीलम शमी राव, एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री चंद्रमौली शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठकों में व्यापारिक नियमों को उद्योग-अनुकूल बनाना, नीतियों को सरल करना और निवेश प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये विचार-विमर्श हुआ। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार

नए उपायों पर सुझाव लिए गए। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह वर्कशॉप की विस्तृत जानकारी दी। सचिव, केन्द्रीय टेक्सटाइल श्रीमती शमी राव ने नीति सरलीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। टास्क फोर्स द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और निवेशकों के लिए बाधाओं को कम करने पर प्रेजेन्टेशन दिये गए। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में इस दिशा में हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। बैठक में उद्योग जगत को हो रही व्यावसायिक दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके समाधान के लिये सरल नीतियों, डिजिटल प्रक्रियाओं और सिंगल-विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

उज्जैन में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन एवं विज्ञान उत्सव का शुभारंभ

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव-2025 अंतर्गत राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव (विकास की बातङ्कविज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ) का शुभारंभ पं. सूर्यनारायण व्यास संकुल, कालिदास अकादमी उज्जैन में प्रातः 11 बजे होगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, दूसरा है 40वां मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन और अंतिम है विज्ञान उत्सव। निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम 'विकास की बात विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ' पर आधारित है। इसमें देशभर के 100 से अधिक शीर्ष वैज्ञानिक भागीदारी कर रहे है। सम्मेलन में वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक विज्ञान और भारतीय प्राचीन विज्ञान परंपरा पर विभिन्न सत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, कृषि एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी, स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं स्किल डेवलपमेंट, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी विषयों पर परिचर्चा होगी। इसके अलावा विज्ञान चौपाल का आयोजन भी होगा।

निदेशक ने बताया कि 40वां मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन अंतर्गत युवा शोधार्थियों द्वारा शोध पत्रों का वाचन होगा। उत्कृष्ट शोध पत्रों को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं फेलोशिप प्रदान की जायेगी। विभिन्न विषयों में 30 से अधिक युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जिसमें प्रथम पुरस्कार 25 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 20 हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार 15 हजार रूपये प्रदान की जायेगी।

बिजली कंपनी ने तेज किया वसूली अभियान, 31 मार्च से पहले करें बकाया राशि का भुगतान

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूली के लिए प्रयास सघन किये जा रहे हैं। बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने, बैंक खाते सीज करने और खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से विजिलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली तेज करने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि ऑडिट द्वारा निकाला गया बकाया और अन्य कारणों से बकाया राशि की वसूली की जाए। जारी निर्देशों में कहा गया कि काटे गये कनेक्शनों की रात में चेकिंग की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न कर सकें।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के विस्तार भवन, कैंसर यूनिट तथा डॉक्टर्स क्वार्टर्स के निर्माण कार्यों को गति दें -उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी विस्तार भवन, कैंसर यूनिट तथा डॉक्टर्स क्वार्टर्स के निर्माण कार्य त्वरित गति से कराये और नियत समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण के साथ पूरे करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, संजय गांधी चिकित्सालय को सर्व-सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। नवीन आवश्यक भवनों के निर्माण के साथ ही चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता तथा डॉक्टर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति की जा रही है ताकि संभाग के किसी भी जिले के मरीज को इलाज के लिये बाहर न जाना पड़े और सभी प्रकार के रोगों का इलाज रीवा में हो सके। उप मुख्यमंत्री ने कैंसर यूनिट के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि 20 करोड़ रूपये की लागत से कैंसर यूनिट का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर यूनिट की स्थापना के साथ ही कैंसर के इलाज के लिये 200 विस्तर का अस्पताल भी बनाया जायेगा। उन्होंने 35 करोड़ रूपये की लागत से निर्माणाधीन सुपरस्पेशलिटी विस्तार भवन कार्य की जानकारी ली तथा कार्य को गति देने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स के लिये 35 करोड़ रूपये से निर्माणाधीन आवासीय क्वार्टस की प्रगति की समीक्षा के दौरान कार्य में धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा निर्माण एजेंसी को निर्देश दिये कि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में कार्य को पुनः समीक्षा करें तथा अपेक्षित प्रगति न होने पर एजेंसी को ब्लैक-लिस्टेड करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाय। उन्होंने निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों की सतत मानिटरिंग करें तथा प्रगति से अवगत करायें। उप मुख्यमंत्री ने बैठक के उपरांत निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती नीता कोल, डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉ. राहुल मिश्रा, अधीक्षक सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल डॉ. अक्षय श्रीवास्तव सहित डॉक्टर्स व निर्माण के अधिकारी व निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में 100 बेड के विस्तार भवन तथा नवीन ओपीडी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने 10 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले विस्तार भवन एवं दोनों भवनों को जोड़ने वाले कॉरीडोर का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आमजन में जागरूकता लाना बहुत जरूरी : मंत्री पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह कार्यक्रम पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के ऑडिटोरियम में हुआ। मंत्री श्री पटेल ने वर्ष 2024 के लिए जिले की टीबी मुक्त 161 ग्राम पंचायतों को प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जिले की अन्य ग्राम पंचायतों को भी टीबी रोग मुक्त पंचायत बनाने के लिये लगातार प्रयास करें। टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आमजन में जागरूकता लाना

बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सरपंच महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। टीबी रोग किन कारणों से होता है और इनसे कैसे बचाव करें? यह जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। टीबी रोग के प्रति ग्रामीणों में जागरूकता रहेगी, तो पंचायत स्वत: टीबी रोग मुक्त हो जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि टीबी का समय पर पता चल जाये और इसका पूरा उपचार हो जाए तो, यह पूरी तरह से रोकथाम और उपचार योग्य रोग है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। टीबी को छुपाएं नहीं और न कोई भी व्यक्ति इसे बताने में संकोच न करे। सरकार इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए नि:शुल्क सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने समाज में इस बीमारी से संबंधित भ्रम की जानकारी देते हुए कहा कि लोग इस बीमारी को कलंक के रूप में देखते हैं। इसे छूने से फैलने वाली बीमारी समझा जाता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को परिवार से दूर रखते है। हमें इन सभी भ्रम को दूर करना होगा। यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा दिनों तक खांसी हो तो जांच अवश्य करायें। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीबी की वैक्सीन लगायी जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

प्रगतिरत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के अधिकारी की होगी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सिहस्थ-2028 के प्रगतिरत उज्जैन में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि निर्माण संबंधी कार्यों में समयबद्ध तरीके से काम किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रगतिरत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रत्येक माह भेजी जाएं। इसकी प्रत्येक 15 दिन में कलेक्टर उज्जैन द्वारा समीक्षा की जाएगी अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गति को बनाए रखना संबंधित विभाग के अधिकारी की जिम्मेदारी है इसके लिए यदि दो शिफ्ट में काम करने की आवश्यकता है तो वह भी करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री नीरज कुमार ने विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। घाट निर्माण के लिए 30 माह का समय सुनिश्चित किया गया है। क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिये कान्हा नदी डायवर्सन की भौतिक प्रगति रिपोर्ट 29 प्रतिशत है। सेवर खेड़ी, सिलार खेड़ी जलाशय का काम भी शुरू हो चुका है। इंदौर उज्जैन सिक्स लेन का कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना है। इसी के साथ उज्जैन मक्सी फोर लेन इंगोरिया उन्हेल और उज्जैन सिंहस्थ बायपास का काम भी प्रगतिरत है। बैठक में पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसी के साथ नगर निगम के मार्ग चौड़ीकरण के कार्यों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण के कार्यों को समन्वय के साथ किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें सभी के सहयोग से कार्य पूर्ण किया जायें। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी निर्माण कार्य में समस्या आ और कलेक्टर को बताएं जिससे समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। प्रो-एक्टिव होकर काम करने की आवश्यकता है जो काम अभी शुरू नहीं हुए हैं और जिनको किया जाना जरूरी है उन कार्यों को भी तुरंत राज्य शासन को भेजें।

मार्च में अवकाश के दिनों में भी खुलेंगे बिजली बिल भुगतान केन्द्र

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में 29 मार्च शनिवार, 30 मार्च रविवार व 31 मार्च ईद-उल-फितर को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त अवकाश के दिनों में भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल ऑफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्य क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है।

कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर बरसे कांग्रेस नेता

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को रीवा पहुंचे। रीवा पहुंचकर उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान वे भाजपा पर हमलावर हुए। अपने 15 मिनट के भाषण और 15 मिनट की प्रेस वार्ता के दौरान जीतू पटवारी तकरीबन 10 मिनट डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर बोले। उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर जमकर निशाना साधा। जीतू ने कहा अगर गूगल किया जाए कि टॉप 10 बलात्कारी, भ्रष्टाचारी नेता कौन हैं और किस पार्टी के हैं तो वो सारे नेता आपको भाजपा पार्टी के मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारी शर्त हार जाऊंगा। अगर मैं गलत निकल जाऊं तो मेरे ऊपर केस कर देना।

उन्होंने कहा कि भोपाल में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला किया जाता है। उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का काम किया जाता है। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लगाया जाता है। हम कदम से कदम मिलाकर पत्रकारों के साथ खड़े हैं।

प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आज स्ट्रेचर पर है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का ग्रह जिला रीवा आज बड़ी स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। अगर सच्चाई जाननी है तो डिप्टी सीएम एक दिन नागपुर जाने वाली बस और ट्रेन में सफर करके दिखा दें। रीवा से 100 में 80 लोग इलाज के लिए नागपुर जा रहे हैं। आपने कैसा प्रदेश बनाया जो हर जगह कोरेक्स ही कोरेक्स है। लोग कोरेक्स की तस्करी से परेशान हैं। डिप्टी सीएम आप अपने मोहल्ले में जाकर देख लो। कौड़ियों के दाम में जमीन का सौदा कर दिया।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि हम सब कांग्रेस के लोग एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने लगते हैं। इस चक्कर में भाजपा आगे निकल जाती है। जबकि ऐसा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। हमारे प्रयासों में कमी रह जाती है। यही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण हैं। किसी भी नेता की हेलिकॉप्टर लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भाजपा में जाए और फिर एक दिन पहले लौट कर आ जाए और पार्टी उसे टिकट दे दे। इस तरह की बात दोबारा नहीं होनी चाहिए।

अजय सिंह ने कहा कि राजेंद्र शुक्ल को राजनीति में मैं लेकर आया था। मैंने उन्हें कांग्रेस में कोषाध्यक्ष का पद दिलाया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें राजनीति में लेकर आया। आज वो उपमुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी है। उधर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि हम कांग्रेस के लोग कभी कभी ऐसा काम करते हैं। जिससे कि दूसरे व्यक्ति को हंसी उड़ाने का मौका मिलता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

मऊगंज की घटना पर जीतू पटवारी ने कहा कि मऊगंज में पुलिस पर हुए हमले, युवक पर हुए हमले दोनों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश में आए दिन पुलिस पीटी जा रही है। इसके लिए प्रदेश की मोहन सरकार जिम्मेदार है। जहां गृह मंत्री तक किसी को नहीं बनाया जा रहा है।

रीवा-सिरमौर मार्ग पर बिना परमिट बस जप्त

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। परिवहन विभाग रीवा ने जांच के दौरान एक बस बिना परमिट जप्त की।यह बस रीवा सिरमौर मार्ग पर संचालित की जा रही थी।

आरटीओ रीवा को यह शिकायत प्राप्त हुई थी की, बस क्रमांक MP 17 P 0598 का बिना परमिट ही संचालन किया जा रहा है।जिसे फ़ौरन संज्ञान में लेते हुए आरटीओ रीवा ने परिवहन सुरक्षा स्क्वाड को बस की जाँच हेतु निर्देशित किया।परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने रीवा सिरमौर मार्ग में जाकर बस को चेक किया बस बिना परमिट पायी गई जिसे जप्त कर परिवहन कार्यालय रीवा में खड़ा कराया गया ।जांच में अन्य यात्री बसों भी पर कार्यवाही की गई जिनमे किराया सूची,ओव्हर लोडिंग, फिटनेस,बीमा,प्रदूषण प्रमाण पत्र की विशेष जांच की गई।जांच में 11 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 46900 रुपये का शमन शुल्क वशूल किया गया।

आईजी गौरव राजपूत ने रीवा ज़ोन की कानून व्यवस्था की कमान संभाल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पुलिस महानिरीक्षक आई पीएस गौरव राजपूत ने रीवा ज़ोन की कानून व्यवस्था की कमान संभाल ली है। बतादें कि 2004 बैच के आईपीएस गौरव राजपूत देश के सबसे कम उम्र के आईजी हैं। युवा आईपीएस गौरव राजपूत हाल ही में पदोन्नत होकर डीआईजी से आईजी बन गए हैं। ऐसे में अब वो देश के सबसे युवा आईजी हैं। महज 41 साल की उम्र में आईजी बनने वाले गौरव राजपूत फिलहाल देश के इकलौते ऐसे आईजी हैं। रीवा ज़ोन में बतौर पुलिस महानिरीक्षक उनकी पदस्थापना पूर्व आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार के सेवानिवृत होने के बाद की गई है। आई पीएस गौरव राजपूत ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर आमद दर्ज कराई। इस दौरान ज़ोन के सभी पुलिस अधीक्षक सहित कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

आपसी भाईचारा एवं सद्भाव पूर्वक मनाएं त्यौहार-कलेक्टर मऊगंज संजय जैन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। आगामी नवरात्रि, ईदुल फित्र त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के उद्देश्य से मऊगंज कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर संजय कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने लोगों से त्योहारों को शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि आपस में मिलजुल कर सद्भाव पूर्वक त्योहार मनाए। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने कहा अफवाहों से बचें और कानून का पालन करें। बैठक में जिले के धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों ने समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए सुझाव भी दिये। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए साफ-सफाई के संबंध बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गये। पर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों के आसपास नगर प्रशासन एवं जनपद द्वारा बेहतर सफाई व्यवस्था के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति समुचित रूप से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। रमजान के दौरान रातों में मस्जिद में आने-जाने में सुविधा हो इसके लिये विशेष व्यवस्था की अपेक्षा की गई। चैत्र रामनवमी के दौरान सभी देवी मंदिरों की साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि सभी धार्मिक पर्वों को शांति और सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनायें। सभी की अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। स्वच्छता बनाये रखना सभी का दायित्व है। कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि धार्मिक स्थलों के आस-पास साफ सफाई, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था बनाने में विशेष सहयोग करें। नवरात्रि एवं ईद तथा महावीर जयंती का पर्व परम्परा के अनुसार अच्छे वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ मनायें । बैठक में मऊगंज जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह, नईगढ़ी नगर परिषद अध्यक्ष नागिता गुप्ता, मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष बृजवासी पटेल, डिप्टी कलेक्टर पवन गोरैया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, एसडीएम मऊगंज बीपी पांडेय, एसडीएम हनुमना कमलेश पुरी सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जल संचय, जन भागीदारी, जन आन्दोलन अभियान में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा-

रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाना है

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)।. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा को विकसित बनाते हुए पानीदार बनाना है। वर्षा के जल को संरक्षित करने तथा प्राचीन जल स्त्रोतों में सुधार कार्य कर जल संरक्षण व संवर्धन के कार्य प्राथमिकता से किये जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पानी की कमी न हो। शुक्ल ने ग्राम पंचायत सगरा में केन्द्रीय जल शक्ति विभाग के सहयोग से बोर के माध्यम से संग्रहित होने वाले भूजल को जमीन के भीतर संचयित किये जाने के कार्य का शुभारंभ किया।

ग्राम पंचायत सगरा में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के जल शक्ति विभाग के सहयोग से रीवा जिले में 100 बोरवेल के माध्यम से संग्रहित होने वाले जल को जमीन के अंदर संचयित किये जाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त जल गंगा अभियान में जल संरक्षण व संवर्धन के कार्य आगामी 3 माह तक नियमित रूप से संचालित होंगे। यह प्रयास है कि वर्षा का जल बर्बाद न हो। जमीन के अंदर इसका संचयन हो तथा जल स्त्रोत भी पानीदार रहे ताकि जिले का भूजल स्तर कम न हो। उन्होंने जल संरक्षण कार्य में आमजनों की सहभागिता की भी अपेक्षा की। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी द्वारा जहां एक ओर हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य हो रहा है वहीं दूसरी ओर जल संचयन, संवर्धन का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन के अंदर के पानी का दोहन न होकर इसका पोषण हो यह इस योजना का लक्ष्य है। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि पानी बचाने के सभी उपाय किये जांय। हम जितना पानी जमीन से लें उतना उसे देने का भी प्रयास करें। गुजरात की टीम के जल संचयन कार्य में सहयोग करें और जल संरक्षण कार्य में सहभागी बनें। उन्होंने बताया कि जल गंगा अभियान अन्तर्गत जिले के तालाब निर्माण के साथ ही मनरेगा से पानी बचाने की संरचनाओं को पूर्ण किये जाने के कार्य कराये जायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने जल संचयन कार्य में गुजरात के दल को प्रशासन के पूर्ण सहयोग की बात कही। इससे पूर्व गुजरात के जल संचयन दल प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि रीवा जिले में 100 बोर कर संग्रहित पानी को चेम्बर बनाकर भूमि के अंदर संचयित किया जायेगा। इस कार्य का शुभारंभ सगरा से किया गया है। कार्यक्रम को प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सरपंच सावित्री राजेश पाल, सीईओ जनपद संजय सिंह, समाजसेवी राजेश पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन व आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे। आभार प्रदर्शन कार्यपालन यंत्री पीएचई संजय पाण्डेय ने किया।

योगी के इशारे पर संविधान लोकतंत्र कानून विरोधी कदम उठा रही करणी सेना

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा संसद के अंदर दिए गए बयान को लेकर उनके आगरा स्थित आवास पर करणी सेना के आक्रामक प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह घर में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की बुलडोजर लेकर गए पहले पुलिस शांत खड़ी रही इसके बाद पुलिस के साथ भी गंभीर रूप से मारपीट किए इसी तरह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सपा कार्यालयों तथा मध्य प्रदेश सपा कार्यालय के समक्ष उग्रतापूर्ण प्रदर्शन किये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के खिलाफ अनर्गल बयान बाजी कर पुतला दहन किये जो बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन के बयान व्यक्तिगत हो सकते हैं उनके बयानों से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो एवं समाजवादी पार्टी को निशाना बनाना योगी सरकार एवं भाजपा की सुनायोजित साजिश है बीजेपी करणी सेना का इस्तेमाल कर रही है जहां-जहां भी हमले हुए बीजेपी के इशारे पर पुलिस शांत खड़ी रही बाद में परिणाम यह हुआ कि पुलिस के जवानों को ही गंभीर रूप से आहत होना पड़ा शिव सिंह ने यह भी कहा कि जो भी हिंसा बीजेपी से जुड़े संगठन करणी सेना व अन्य संगठनों ने मिलकर किया है वह गैरकानूनी है संगठन का यह कृत्य संविधान लोकतंत्र कानून विरोधी है कानून किसी को ऐसी इजाजत नहीं देता है सांसद के बयान से यदि कोई आहत हुआ है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं शिव सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को आजादी के पूर्व का एवं आजादी के समय का इतिहास भी याद होना चाहिए हम समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी सरकार व ऐसे संगठनों से डरने वाले नहीं है यदि भाजपा सरकार कानून संविधान लोकतंत्र को मानती है तो तत्काल ऐसे घटना कारित करने वाले संगठनों के लोगों के खिलाफ कानूनी एवं दंडात्मक कार्यवाही करे।

विधि महाविद्यालय में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में शासकीय विधि महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सों श्रीमती कंचन गुप्ता ने पाक्सों अधिनियम, घरेलू हिंसा, भरण पोषण की जानकारी दी।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि विधि के विद्यार्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं उद्देश्यों को पूरे समाज में प्रसारित कर विधिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। उन्होंने विधि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में प्रकाश डाला। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. योगेन्द्र तिवारी ने एनडीपीएस कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में मंजूर अहमद मंसूरी, आनंद पाण्डेय, अनीश पाण्डेय, महाविद्यालय के प्रध्यापकगण तथा छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रबीन्द्र तिवारी द्वारा किया गया। आभार डॉ. भोला प्रसाद साहू ने किया।

भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने वाले को मिलेंगे दो लाख रुपए

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। शिशु का लिंग निर्धारण परीक्षण करना दण्डनीय अपराध है। भ्रूण लिंग जाँच की सूचना देने वाले को दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मुखबिर पुरस्कार योजना के तहत दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि भ्रूण लिंग जाँच की सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उसकी सूचना के आधार पर प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत होते ही एक लाख 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें 50 हजार रुपए की राशि सूचना देने वाले को, 25 हजार रुपए की राशि पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के जिला नोडल अधिकारी को तथा 50 हजार रुपए की राशि अभियोजन अधिकारी को दी जाएगी। न्यायालय में अपराध सिद्ध होने पर 75 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें सूचना देने वाले को 30 हजार रुपए, नोडल अधिकारी को 15 हजार रुपए तथा अभियोजन अधिकारी को 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत स्टिंग ऑपरेशन करने पर स्टिंग के सफल होने तथा सत्यापन के बाद मुखबिर को 50 हजार रुपए, सहयोगी महिला को 20 हजार रुपए तथा अन्य सहयोगी को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।

स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी में 'दाग'

रीवा. यह तस्वीर मार्तंड स्कूल तिराहे की है जहां स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कबाड़ से जुगाड़ पद्धति में एक महिला सफाई कर्मी का स्टेचू लगाया गया है लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने इस स्टैचू पर ही पोस्टर टांग दिया। भले ही हरकत छोटी लग रही हो लेकिन निश्चित तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। जो शहर की सुंदरता और नगर निगम के प्रयासों पर दाग लगा रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने वार्ड क्रमांक 38 में संजीवनी क्लीनिक का किया भूमिपूजन

विकसित भारत का सपना स्वस्थ भारत से ही पूरा होगा

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने वार्ड क्रमांक 38 में चोपड़ा स्कूल परिसर में संजीवनी क्लीनिक भवन का भूमिपूजन किया। इसका निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह रीवा शहर का दसवां संजीवनी क्लीनिक है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ संजीवनी क्लीनिक बन जाने से लगभग दो हजार परिवारों को प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। विकसित भारत का सपना स्वस्थ भारत से ही पूरा होगा। सरकारी अस्पतालों में हजार तरह की दवाएं तथा तीन सौ से अधिक जाँचों की निःशुल्क सुविधा है। निरोगी काया अभियान के तहत मधुमेह, ब्लडप्रेशर, फैटीलीवर तथा कैंसर जैसे रोगों की निःशुल्क जाँच की जा रही है। आमजनता इनका लाभ उठाकर अपने आप को स्वस्थ रखे। कैंसर का भी समय पर पता लग जाता है तो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल जबसे खुला है तब से नागपुर जाने वालों की संख्या आधी हो गई है। इस अस्पताल में कल ही दो किडनी ट्रांसप्लांट के सफल आपरेशन हुए हैं। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और ओपनहार्ट सर्जरी के आपरेशन भी हो रहे हैं। लगभग दो माह में कैंसर यूनिट भवन का निर्माण पूरा करके दो सौ बिस्तर का कैंसर अस्पताल शुरू हो रहा है। इसमें 60 लाख रुपए की लागत से लीनियर मशीन लगाई जाएगी जिसमें सभी तरह के कैंसर की जाँच हो सकेगी। संजय गांधी हास्पिटल में नए वार्ड के निर्माण तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए 322 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल में 15 करोड़ रुपए की लागत से नई एमआरआई मशीन तथा कैथलैब लगाई जा रही है। रीवा में उपचार की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनसे आगामी 50 सालों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी के कार्यों से रीवा की नई पहचान बनी है। आज वार्ड 38 के निवासियों को संजीवनी क्लीनिक के रूप में सौगात मिल रही है।

कार्यक्रम में मण्डल अध्यक्ष हेमलता सिंह, पार्षद नीलू कटारिया, पार्षद राजबहोर साकेत, पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, राजीव शर्मा, विवेक मिश्रा, साकेत बिहारी, कार्यपालन यंत्री नगर निगम राजेश सिंह, डॉ बीआर चौधरी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह ने किया।

मुख्यमंत्री आज सिंगल क्लिक से करेंगे अनुग्रह राशि का वितरण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। श्रम विभाग के तहत संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के हितग्राहियों को 28 मार्च को अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य स्तरीय समारोह से सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुग्रह राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश भर के 23162 मजदूर परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से एनआईसी केन्द्र रीवा और मऊगंज में आरंभ होगा। इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी प्रिया अग्रवाल ने बताया कि सिंगल क्लिक के माध्यम से रीवा जिले के 485 हितग्राहियों एवं मऊगंज जिले के 194 हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी मऊगंज जिले के दो हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला और विकासखण्ड स्तर पर सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि संबल योजना के तहत पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अंत्येष्टि सहायता के रूप में पाँच हजार रुपए दिए जाते हैं। मजदूर की सामान्य मृत्यु पर उनके परिजनों को दो लाख रुपए तथा दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

विचार

सुनीता विलियम्स–साहस से छुआ आसमान

अगर देखना चाहते हो मेरे हौसलों की उड़ान तो आसमान से कह दो कि और ऊँचा हो जाए। ये पंक्तियाँ निश्चित ही ऐसा आभास कराती हैं कि यह असंभव जैसी बात है। क्योंकि आसमान में उड़ने वाली बात किसी ऐसे सपने जैसी ही लगती है, जो पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति के पास साहस और धैर्य है तो वह असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स ने ऐसा ही एक कीर्तिमान करके दिखाया है। धरती पर रहने वाली सुनीता ने अपने साहस और धैर्य से आसमान को छूने को साहसी कार्य किया है। यह एक ऐसा कीर्तिमान है जो भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है। जो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक दिशा बोध बनेगी। आज अंतरिक्ष विज्ञान जगत के लिए सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है, जिसके साथ विज्ञान को देने के लिए बहुत कुछ है। जिनकी गाथा कहते कहते लोगों के मुंह थक जाएंगे, पर गाथा ख़त्म नहीं होगी। सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर सहित चार अंतरिक्ष यात्री जब धरती पर लौटे तो अमेरिका में खुशी का वातावरण था, तो भारत में भी असीमित उल्लास था। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं, इसलिए यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत का भी मान बढ़ाया है। सुनीता विलियम्स केवल नौ दिन के लिए अंतरिक्ष की सैर पर गई थीं, लेकिन यह क्या मालूम था कि यह नौ दिन की यात्रा नौ माह और चौदह दिन की हो जाएगी। जाहिर है यात्रा सरल नहीं थी। क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव रहता है। हालांकि सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी। हम जानते हैं धरती से वायुमंडल की परिधि समाप्त होने के बाद अंतरिक्ष की दुनिया प्रारम्भ होती है। अंतरिक्ष के बारे में कहते हैं कि मानव आकृति अधर में ही लटकी रहती है। अगर कोई यात्री अंतरिक्ष यान में भी गया है, तो भी उसे आधार नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वजनहीन हो गए हैं। अंतरिक्ष में चल फिर नहीं सकते। बस तैरते से रहते हैं। ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में जाना निश्चित ही अत्यंत दुष्कर कार्य है। भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथ गए बुच विलमोर ने जिस साहस का परिचय दिया, वह वास्तव में काबिले तारीफ़ है। लेकिन एक बात यह भी है कि अंतरिक्ष में जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहां का जीवन पृथ्वी से बहुत भिन्न है। अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों का यान ज़ब भटक गया था। तब उनके मन में भी कई तरह के सवाल उठे होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह पता नहीं होता कि वे धरती पर लौटेंगे भी या नहीं। या अंतरिक्ष में कब तक यूँ ही घूमते रहेंगे, इसका भी पता नहीं, लेकिन एक जिजीविषा थी, जो उन सबको जीने का उल्लास दे रही थी। कहते हैं कि जिसके मन में जीने का उत्साह हो तो समस्याएं सरल होती चली जाती हैं।

योगी राज में सर्वांगीण विकास के पथ पर तेज़ी से अग्रसित होता उार प्रदेश

उार प्रदेश के मुयमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उार प्रदेश के मुयमंत्री के रूप में लगातार आठ वर्ष तक कार्य करने का एक नया कीर्तिमान बना दिया हैं। सत, ईमानदार व एक विजनरी प्रशासक वाली कार्यशैली के दम पर मुयमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश व देश के साथ-साथ पार्टी में भी एक भरोसेमंद ब्रांड बनकर के स्थापित हो गये हैं। मुयमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का आलम यह हो गया है कि एक तरफ तो देश के हर राज्य के चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की मांग निरंतर होती है, वहीं दूसरी तरफ अब योगी की कार्यशैली के देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी आये दिन चर्चाएं होती रहती हैं।

वैसे भी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले आठ वर्षों के अपने शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के शासन व पुलिस–प्रशासन की कार्यशैली में जबरदस्त ढंग से सुधार करते हुए, दशकों से सरकारी तंत्र की तरह–तरह के हस्तक्षेप, माफियागिरी, भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कुंद हो चुकी धार को तेज करते हुए, उसे आम जनमानस व देश के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य बखूबी किया है, जोकि बेहद ही काबिले–तारीफ है और जिसका परिणाम अब स्पष्ट रूप से शासन व पुलिस–प्रशासन की कार्यशैली में आये सकारात्मक बदलाव के रूप में राज्य के आम जनमानस को नज़र आने लगा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दमदार ढंग से सत्ता में आठ वर्ष का अपना लंबा कार्यकाल 25 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जोकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि इतिहास में दर्ज हो गयी है। देश के हर कोने में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के बड़ी संख्या में आम व खास लोग प्रसंशक होते जा रहे हैं। शानदार कार्यशैली के दम पर अपने प्रथम कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश व दुनिया में %बुलडोजर बाबा% के नाम से मशहूर हो गए थे। उनके बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े माफियाओं की सल्तनत को ध्वस्त करने का कार्य बेखौफ होकर के किया है, आज देश के अधिकांश राज्य अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की नक़ल करने में लगे हुए हैं, जो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

नियम–कायदे व कानून पसंद देशभक्त देशवासियों व उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए योगी आदित्यनाथ के प्रथम कार्यकाल की तरह ही दूसरे कार्यकाल से भी लोगों को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं। जिस पर जनता की अदालत में योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी पूरी तरह से खरे उतरते नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने अब उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल कर के देश में दूसरे पायदान पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

जो लोग यूपी की अर्थव्यवस्था को %वन ट्रिलियन इकनॉमी% करके देश में विकास की अग्रणी पंक्ति पर स्थापित होता देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ उन लोगों के सपने को जल्द से जल्द ही धरातल पर सरकार करने के लिए दिन–रात जुटे हुए हैं और वर्ष 2029 तक उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा भी तय कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह भी अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल्द से जल्द देश की अर्थव्यवस्था को %फाईव ट्रिलियन इकनॉमी% की बनते हुए देखने का जो सपना देखा हैं, इस सपने को पूरा करने का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर ही गुजरता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से सभी क्षेत्रों का बिना किसी भेदभाव के विकास होगा, उतनी ही तेजी के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के %फाईव ट्रिलियन इकनॉमी% बनने का भी रास्ता साफ होगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व देश के देशभक्त आम जनमानस का सपना भी धरातल पर साकार होता नज़र आयेगा।

वैसे भौगोलिक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े क्षेत्रीय विस्तार वाला राज्य है, जिसके चलते पूरे राज्य का सर्वांगीण विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बना कर, उन्हें तेज़ी से धरातल पर अमलीजामा पहनाने का कार्य बखूबी किया है। धरातल पर जाकर के देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास को तेज गति देने वाले आधारभूत ढांचे का निर्माण कार्य योगी राज में बहुत ही तेजी से जगह–जगह चल रहा है। प्रदेश के गांव, कस्बे व शहरों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार धरातल पर निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की ताक़त उसकी एकजुटता में है, जिसके चलते ही उत्तर प्रदेश के चारों हिस्से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों व शहरों में बड़े पैमाने पर विकास का एक पूरा सशक्त आधारभूत ढांचा योगी राज में तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब योगी के प्रयासों से ही डबल इंजन की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के मार्ग, सड़क मार्ग, हाईवे, एक्सप्रेस–वे, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, रेपिड रेल, जल मार्ग, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, औधोगिक क्षेत्र, राज्य में दूर दराज के गांव तक भी इंटरनेट, अत्याधुनिक कोल्डस्टोरेज की सुविधा, %वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट% आदि के सपने को धरातल पर मूर्त रूप दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने देश व दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों के धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से राम मंदिर निर्माण, अयोध्या, काशी व मथुरा का विकास, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक महाकुंभ नगरी का निर्माण करके लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों को संगम पर स्नान करा कर के, उत्तर प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की के पंख लगा कर के राज्य में विकास के नये आयाम स्थापित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में ही बेहद सख्त व प्रभावी क़दम उठाए हैं। उनकी सख्ती के चलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी सरकार के पिछले आठ वर्षों के कार्यकाल में माफिया व अपराधियों की कमर तोड़ने का कार्य बखूबी से किया है। योगी सरकार ने राज्य में 222 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने कार्य किया है। मुठभेड़ के दौरान 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं आम जनमानस में खौफ पैदा करने वाले 79,984 खतरनाक अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2017 से वर्ष दिसंबर 2024 तक चिन्हित 68 माफियाओं के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए 73 अभियोगों में 31 माफियाओं और 74 सह अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलवाने का कार्य भी किया है और दो अपराधियों को सजा ए मौत फांसी भी सुनाई गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह रणनीति उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाने के सपने को धरातल पर साकार करने का कार्य करती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को समय से रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा आदि जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि उसको पूरा करने के लिए सरकार में बैठे लोगों के बेहतरीन विजन व राजकोष में अथाह धन की आवश्यकता होती है, जिस जिम्मेदारी को योगी सरकार ने बखूबी संभालने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छी बात यह है कि योगी राज में यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ गया है। राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अपराध योगी राज में कम होने के चलते, यूपी फिर से देश व दुनिया के निवेशकों की पसंद बनने लगा है, योगी की नीतियों से यूपी सरकार की खाली झोली अब खजाने से भरने लगी है। योगी सरकार की नीतियों व सहयोगात्मक रवैये के चलते राज्य में अब बहुत बड़े पैमाने पर देश व दुनिया से निवेश आना शुरू हो गया है। राज्य में औधोगिक विकास एक बार फिर से तेज़ गति पकड़ने लगा है।

लगातार बढ़ रहा हौसला, तीन साल में साइबर ठगी में बीस गुणा बढ़ोत्तरी

मोबाइल पर नंबर मिलाते ही आजकल साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन या ब्लेक मेलिंग से सतर्क रहने का संदेश सुनने को मिलता है। इस सबके बावजूद भारत सरकार द्वारा ठगी के जारी आंकड़ें ना केवल चेताने वाले हैं अपितु लगता है जैसे ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया वाले हालात बनते जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि साइबर ठगी के इन रुपों से सबसे अधिक शिकार पढ़े लिखे और समझदार लोग ही हो रहे हैं। लाख समझाने के बावजूद एक ओर ठगों के हौसले बुलंद है तो ठगी के शिकार होने वाले लोगों की संख्या और राशि में मल्टीपल बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों को देखे तो पिछले तीन साल में ही ठगी के नए अवतार से ठगी की राशि 20 गुणा बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत के दो महीनों में ही 17 हजार 718 से अधिक मामलें दर्ज हो चुके हैं और 210 करोड़ 21 लाख रु. से अधिक की ठगी हो चुकी है। यह तो साल की शुरुआत के हाल है। पिछले तीन साल के आंकड़ों पर नजर ड़ाले तो हालात की गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। साल 2022 में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की ब्लेक मेलिंग, ऑनलाइन ठगी आदि के 39925 मामलों में 91 करोड़ 14 लाख की ठगी हुई थी जो एक साल बाद ही 2023 में बढ़कर 60676 हो गई और इसमें 339 करोड़ रु. की राशि की ठगी हो गई। मजे की बात यह है कि लाख प्रयासों के बावजूद 2024 की बढ़ोतरी तो और भी चिंतनीय रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 2024 में एक लाख 23 हजार 672 मामलें दर्ज हुए और 1935 करोड़ 51 लाख रु. की ठगी हो गई। यह तो वे मामलें हैं जो पुलिस में दर्ज हुए हैं जबकि हजारों मामलें ऐसे भी होंगे जिनमें मामलें दर्ज कराए ही नहीं गए होंगे। खास बात यह है कि ठगी के केन्द्र व ठगी के तरीके से वाकिफ होने के बावजूद यह होता जा रहा है। हांलाकि झारखण्ड के जमातड़ा से ठगों के तंत्र को तोड़ दिया गया पर देश में एक दो नहीं अपितु 74 जिलों में इस तरह की ठगी करने वालों के हॉटस्पॉट विकसित हो गए। झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के केन्द्र पहले पांच प्रमुख सेंटर विकसित हो गए।

ऐसा नहीं है कि साइबर या इससे जुड़ी ठगी हमारे यहां ही होती है अपितु देखा जाए तो यह आयातित ठगी का तरीका है। साइबर या यों कहें कि इस तरह की ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान पर है तो यूक्रेन दूसरे पायदान पर बना हुआ है। इनके बार चीन, अमेरिका, नाइजेरिया और रोमानिया का नंबर आता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है साइबर ठगों के सारी दुनिया में हौसले बुलंद है। लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। लोगों की कमजोरी को यह समझते हैं और उसी कमजोरी के चलते पढ़े लिखे और होशियार लोगों को भी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते

हैं। जाल ऐसा की यह समझते हुए कि ऐसा आसानी से होता नहीं है फिर भी चक्कर में फंस ही जाते हैं और ठगों के आगे सरेण्डर होकर लुट जाते हैं।

जहां तक हमारे देश की बात करें तो साइबर ठग या तो किसी तरह का लालच देकर लिंक भेजकर ठगी करते हैं तो दूसरी और ड़रा धमकाकर आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। सरकार प्रचार के सभी माध्यमों से बार बार व लगातार आगाह कर रही है कि ठगों द्वारा ड़राने वाले तरीके वास्तविक नहीं है। बैंक कभी भी बैंक डिटेल या ओटीपी ऑनलाइन नहीं मांगते पर पता नहीं कैसे ठगों के जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। ओटीपी देदेते हैं तो लिंक खोलने के लिए लाख मना करने के बावजूद लिंक खोलकर लुट जाते हैं। पुलिस अधिकारी बन कर जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का रास्ता अपनाया जा रहा है उस संबंध में अवेयरनेस अभियान के बावजूद ठगी का शिकार होने वालों की संख्या या राशि में कमी नहीं हो रही है। डिजिटल अरेस्ट में डॉक्टर, रिटायर्ड जज, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी सहित संभ्रात वर्ग के लोगों को आसानी से जाल में फंसाकर ठगी हो रही हैं वह भी करोड़ों तक की ठगी के उदाहरण मिल रहे हैं। झूठे मामलों में परिजनों को फंसने से बचाने का झांसा देकर ठगी हो रही है। मजे की बात यह है कि इस स्तर तक ड़र या भयाक्रांत हो जाते हैं कि किसी अन्य या पुलिस से समस्या साझा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और ठगी के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामलें तो दिनों–दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल इसमें पुलिस, सरकारी जांच एजेंसी या प्रवर्तन निदेशालय के नकली अधिकारी बन कर इस कदर ड़रा देते हैं और मजे की बात यह कि एक दो दिन नहीं अपितु कई दिनों तक लगातार ऑडियो या वीडियो कॉल करके ठगी का शिकार बना लेते हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। सरकार व वित्तदायी संस्थाओं द्वारा मीडिया के माध्यम से सजग किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखण्ड के बड़े केन्द्र जमातड़ा को लगभग समाप्त कर ही दिया है। पर देश में 74 हॉट स्पॉट विकसित हो गए हैं। इनमें हरियाणा का नूंह, राजस्थान का डीग, झारखण्ड का देवघर, राजस्थान का अलवर और बिहार का नालंदा पहले पांच हॉट स्पॉट हो गए हैं। मीडिया द्वारा भी समय समय पर स्ट्रिंग कर इस तरह के केन्द्रों को एक्सपोज किया है पर ठगी कम होने को ही नहीं है। दरअसल आमनागरिकों को भी सजग होना ही होगा। अनजान नंबरों पर बात ही ना करें। ज्योंही कोई डराये धमकायें तो बहकावें में आने के स्थान पर पड़ताल करें। इस तरह के हालात सामने आये तो परेशान होने के स्थान पर परेशानी को साझा करें, पुलिस का सहयोग लेने में भी संकोच ना करें। देखा जाए तो सजगता ही इस समस्या का समाधान हो सकती है।

छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर ((निप्र))। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कई नेताओं पर ब्ठप् ने छापेमार कार्रवाई की। इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, हमने महादेव सट्टा के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग भी की थी, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में उनके प्रिय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के यजमान बने हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो प्रदीप मिश्रा से मदद ले लेती, मिश्रा एक मंत्र फूंकते और तुरंत उनको दुबई से भारत ले आते, लेकिन वह भी नहीं हो पाया।

प्रदर्शनकारियों पर थ्प्त् दर्ज हो सकती है :छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में चल रही ब्ठप् जांच खत्म हो गई हैं। बुधवार शाम जांच के बाद वापस लौट रही एजेंसी की गाड़ियों को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान अधिकारियों ने इसका वीडियो बनाया, जिससे प्रदर्शनकारियों पर थ्प्त् दर्ज हो सकती है। वीडियो में भूपेश बघेल के बंगले से जांच टीम बैग लेते निकल रही थी, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की।

जिला स्तर पर होगा कांग्रेस का प्रदर्शन: जिला स्तर पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि म्क् के बाद अब ब्ठप् ने महादेव सट्टा एप मामले में बुधवार को भूपेश बघेल समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी थी। कांग्रेस ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई करार देते हुए आज यानी 27 मार्च को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

भूपेश बोले - ब्ठप् सिर्फ फोटोकॉपी पर साइन करवाकर ले गई ब्ठप् रेड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ठश्रच् को लेकर कहा कि 30 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके भाषण का कंटेंट तैयार करने के लिए ये रेड डाली गई है। मेरे घर में कुछ नहीं मिला, तो ब्ठप् अधिकारी मेरे 3 मोबाइल ले गए। बघेल ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। 15 दिन पहले म्क् ने छापा मारा था, अब ब्ठप् आ गई। उन्हें पहले से पता था कि कुछ मिलने वाला नहीं है। जब म्क् कुछ नहीं निकाल पाई तो ब्ठप् भी सिर्फ फोटोकॉपी पर साइन करवाकर ले गई। उन्होंने आगे कहा, ब्ठप् ने मेरी सभी प्रॉपर्टी और जमीन के ओरिजनल दस्तावेज ले लिए। ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी पहले रमन सिंह सरकार ने जांच कराई थी, फिर म्क् ने, और अब ब्ठप् कर रही है। अगर कुछ गलत होता तो पहले ही सामने आ चुका होता। ये सिर्फ चुनावी राजनीति के तहत किया जा रहा है।

म्क् के बाद अब ब्ठप् की कार्रवाई : बता दें कि 10 मार्च को महादेव सट्टा एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (म्क) ने जांच की थी, लेकिन अब ब्ठप् ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए बुधवार को रायपुर, भिलाई सहित प्रदेशभर में 24 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। ब्ठप् ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित निवासों में छापा मारा और उनके काफिले की जांच भी करते नजर आए। वहीं भूपेश बघेल के करीबी लोगों के घरों पर भी छापे मारे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, पूर्व पै अधिकारी अनिल टुटेजा, पूर्व ٖक् मनीष बंछोर, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया सहित कई अन्य नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर ब्ठप् ने जांच की।

महादेव एप घोटाले की जांचरू जानिए पूरा मामला: छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच ब्ठप् को सौंप दी थी। म्क् ने जनवरी 2024 में इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसे आर्थिक अपराध शाखा (म्ॅ) और एंटी करप्शन ब्यूरो (।ब्ठ) को भी सौंपा गया था। मार्च 2025 में ।ब्ठ ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत केस दर्ज किया गया था। ब्ठप् की टीम ने बुधवार तड़के छापेमारी शुरू की और पूरे दिन तलाशी अभियान जारी रखा। इस दौरान अधिकारियों के घरों, दफ्तरों और अन्य ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त किए गए। ब्ठप् ने महादेव एप घोटाले से जुड़े बैंक ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी डील और अन्य आर्थिक लेन-देन की जांच के लिए कई डिजिटल डिवाइसेज भी जब्त की हैं।

कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन : ब्ठप् और म्क् की कार्रवाई के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और पुतला दहन करेंगे। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को 'लोकतंत्र के खिलाफ साजिश' बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई बीजेपी सरकार के इशारे पर की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

सब्जी का मोलभाव करने पर मर्डर

कद्दू का रेट कम करने कहा तो भड़का दुकानदार, ग्राहक को उठाकर सिर के बल पटका

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजधानी रायपुर में नशीली दवाइयों की होम डिलीवरी किए जाने का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने गुजरात से स्पीड पोस्ट के जरिए नशीली दवाई मंगवाई थी और उसे शहर में होम डिलीवर करने वाले थे। इसी बीच पुलिस को भनक लगी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। 25 मार्च को सैबी ए बेंजामिन (45) और अश्वनी पाल (40) दोनों अशोक विहार के मैदान के पास स्कूटी से पहुंचे थे और कही जाने की फिराक में थे। उनके कब्जे से 200 नग प्रतिबंधित नशीली स्पास्मो टेबलेट मिली है।

घेराबंदी कर पकड़ा गया : पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने नशीली दवाओं को गुजरात से मंगवाया था। ₹ाइम ब्रांच को सूचना मिली कि ग्राम खादी उद्योग भंडार अशोक विहार पास दोपहिया वाहन सवार दो अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखें। इसके बाद पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया और घेराबंदी में पकड़ लिया।

आरोपियों को दवाई मंगवाने की ट्रेनिंग थी : सैबी पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था वहां से उसने देशभर से दवाई मंगवाने की ट्रेनिंग मिल गई थी। जिसके बाद वह नशीली दवाइयों को गुजरात से स्पीड पोस्ट से मंगवाने लगा। पुलिस ने आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक स्कूटी समेत 1 लाख का माल जब्त किया गया है। दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले है। आरोपी अश्वनी पाल पूर्व में भी उड़ीसा से धोखाधड़ी के प्रकरण में जेल जा चुका है। फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

2 ठेकेदारों पर केस 217 को नोटिस देकर मांगा जवाब

मीडिया ऑडीटर, कोरबा (एजेंसी)। भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) ने एसईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा किए गए पीएफ घोटाले को उजागर किया है। मामले में कोरबा की चार और मनेंद्रगढ़ की एक परियोजना में कार्यरत कुल 219 ठेकेदारों ने ईपीएफ के नियमों का पालन नहीं किया है। इनमें से 2 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने के साथ ही अन्य 217 को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने या जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। ईपीएफओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि एसईसीएल के अंतर्गत काम कर रहे बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन किए हैं। इन ठेकेदारों ने पात्र कर्मचारियों से काम तो लिए पर उनका न तो पंजीयन कराया और ना ही उनके नियमित योगदान की राशि ही भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराए। यही नहीं, उक्त ठेकेदारों ने आवश्यक रिटर्न तक दाखिल नहीं कर कर्मचारियों के हितों का उल्लंघन करते हुए शासन के मद की राशि भी जमा नहीं कर क्षति पहुंचा रहे हैं। ठेकेदारों ने एसईसीएल के संबंधित परियोजनाओं के कार्यालयों में फर्जी पीएफ चालान प्रस्तुत कर बिना सत्यापन के ही भुगतान प्राप्त करते रहे हैं। ईपीएफओ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कानून की धारा 4ए के तहत एसईसीएल मुख्य नियोक्ता के रूप में अपने ठेकेदारों की वैधानिक जिम्मेदारियों की निगरानी करने का उत्तरदायी है।

दंतेवाड़ा आ सकते हैं अमित शाह

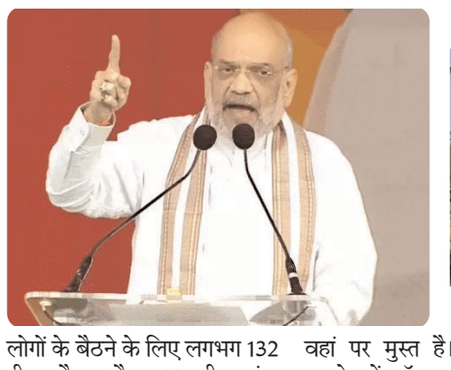

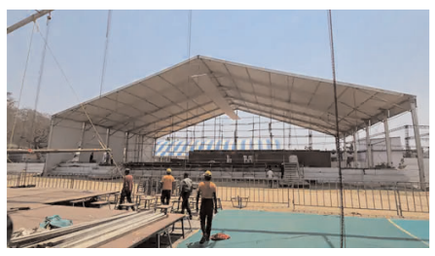

मीडिया ऑडीटर, जगदलपुर (निप्र)। अप्रैल के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा आ रहे हैं। वे यहां बस्तर पंडुम के समापन कार्य₹म में शिरकत करेंगे। फिलहाल शाह के दौरे की फाइनल तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन 4 या फिर 5 अप्रैल को उनका दौरा हो सकता है। जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। बताया जा रहा है कि वे नक्सलियों का एनकाउंटर करने वाले जवानों से भी मिल सकते हैं। नक्सल मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले सकते हैं। चौत्र नवरात्र में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने मंदिर भी जा सकते हैं। हालांकि, शाह के दौरे का फाइनल शेड्यूल जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा।

हाई स्कूल मैदान में होगा कार्य₹म: दरअसल, दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में अमित शाह के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। यहां लोगों के बैठने के लिए लगभग 132 फीट चौड़ा और 332 फीट लंबा विशाल डोम बनाया जा रहा है। वहीं 72 फीट चौड़ा और करीब 40 फीट लंबा मंच भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 65म300 के 2 और डोम बन रहे हैं जिसमें स्टॉल लगाए जाएंगे।

सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम :जिस हाई स्कूल मैदान में कार्य₹म होना है उस पूरे इलाके में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं। जवानों की टीम वहां पर मुस्त है। आस-पास के इलाके में डॉग स्क्वायड की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है।

साढ़े 3 महीने बाद दूसरा दौरा: लगभग साढ़े 3 महीने के बाद अमित शाह दूसरी बार बस्तर आएंगे। इससे पहले वे 15 दिसंबर 2024 को बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर आए थे। यहां वे बस्तरिया ओलंपिक के समापन में शामिल हुए थे। अब वे दंतेवाड़ा आएंगे और बस्तर पंडुम के समापन में शामिल होंगे।

शाह की डेड लाइन, 2026 तक करेंगे नक्सलवाद खत्म: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब साढ़े 3 महीने पहले जगदलपुर आए थे तब उन्होंने मंच से कहा था कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हिंसा करने वाले लोगों से हमारे जवान निपटेंगे

वर्जिनिटी टेस्ट महिलाओं के अधिकारों का हनन

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प%ी की वर्जिनिटी टेस्ट कराने की मांग को महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। टेस्ट की मांग को असंवैधानिक बताते हुए पति की याचिका खारिज की गई है। दरअसल, पति अपनी प%ी के कैरेक्टर पर शक करता था। वहीं प%ी ने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया। जिसके बाद पति ने प%ी की वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है, तो वह अपना मेडिकल परीक्षण करा सकता है। लेकिन प%ी पर ऐसा आरोप थोपना अवैधानिक है।

रायगढ़ जिले के रहने वाले एक युवक की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विवाह के कुछ दिनों तक पति-प%ी के बीच संबंध ठीक रहा। लेकिन, कुछ महीने बाद ही पति-प%ी के बीच विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद पति-प%ी अलग रहने लगे।

इस बीच महिला जुलाई 2024 में रायगढ़ फैमिली कोर्ट पहुंचकर पति से भरण-पोषण के लिए 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने के लिए याचिका लगाई। प%ी ने यह आरोप भी लगाया कि उसका पति नपुंसक है, जिसके कारण वह शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। उसे और परिवार वालों को धोखे में रखकर शादी की गई। वहीं, पति ने आरोप लगाया कि प%ी का उसके बहनोई से अवैध संबंध है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पति की दलील को खारिज कर दिया। यह मामला अभी लंबित है।

बदहाल सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण पर भड़के

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सफाई की बदहाल व्यवस्था, अति₹मण और नालियां जाम होने पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। चीफजस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं।

स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है फिर भी गंदगी पसरी रहती है। वहीं, अधिकारी टी शर्ट और जींस पहनकर निरीक्षण कर फोटो खिंचाते रहते हैं। पत्थलगांव सड़क मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो काम एक पेन से सकता है, वह आप नहीं करते, सिर्फड्रामा करने जाते हैं। डिवीजन बेंच ने 9 अप्रैल से पहले कलेक्टर-एसपी को शपथपत्र के साथ जवाब देने का आदेश दिया है।

दरअसल, हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इसमें नगर निगम के वार्ड ₹मांक 14 और 15 शुभम विहार कॉलोनी सहित मोहल्लों में जलभराव की गंभीर समस्या है। नालियां जाम हैं, जिससे गंदगी के कारण बदबू फैल रही है और डेंगू का खतरा बढ़ गया है। सीवरेज पाइपलाइन भी जाम है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह जरहाभाठा ओमनगर की सफाई व्यवस्था है। जहां पूरा इलाका कचरों से भरा पड़ा है। नगर निगम हर महीने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा, फिर भी कई वार्डों में गंदगी फैली हुई है। लोगों की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग और संबंधित कर्मचारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे। जबकि वार्ड पार्षद समेत आम लोग लगातार समस्या की जानकारी दे रहे हैं। वहीं, दिव्यांगों के लिए बनाए गए फुटपाथ की दुर्दशा है। फुटपाथ पर सामान्य लोग भी नहीं चल सकते। स्लैब टूटे हुए हैं और कचरा भरा पड़ा है। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। 40 करोड़ रुपए से फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सड़कें बनीं, लेकिन रखरखाव के अभाव में सब खराब हो गया। साइकिल ट्रैक पर दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं।

महामाया मंदिर के कुंड में कछुओं की मौत पर जताई चिंता

महामाया मंदिर के तालाब में 2 दर्जन कछुओं की मौत पर भी हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। मीडिया में आई खबर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने तालाब में मछली पकड़ने का जाल डाला, जिसमें कछुए फंसकर मर गए।

मंदिर परिसर ब्ब्ज्ट निगरानी में है, फिर भी यह घटना हो गई। इससे श्रद्धालुओं में आ₹ोश है। वन विभाग की टीम मृत कछुओं को पोस्टमॉर्टम के लिए ले गई है। डीएफओ ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

डिवीजन बेंच ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर सवाल उठाते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की जवाबदेही तय करने की बात कही। उन्होंने कहा, मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन क्या कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना कैसे हुई।

भिलाई निगम में 801 करोड़ 78 लाख का बजट पेश, पार्षदों ने किया हंगामा

मीडिया ऑडीटर,भिलाई (एजेंसी)। भिलाई नगर निगम में गुरुवार को मेयर नीरज पाल ने 801 करोड़ 78 लाख 45 हजार का बजट पेश किया। जिसमें से 619 करोड़ 55 लाख 47 हजार शहर के विकास में खर्च किए जाएंगे। इससे पहले, सभी पार्षदों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव लिए गए थे। इस बजट के दौरान सत्ता, विपक्ष और निर्दलीय पार्षदों ने गलत तरीके से विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के पार्षद दया सिंह ने निगम कमिश्नर पर जमकर चुटकी ली, तो वहीं निर्दलीय पार्षद हरिओम तिवारी उनकी बात ना सुने जाने पर नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर चले गए।

काफी हंगामेदार रही बजट: बजट अभिभाषण के बाद विशेष सभा में हंगामा शुरू हो गया। बजट बैठक काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने निगम सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष के पार्षद लक्ष्मीपति राजू सभी प्रस्ताव को पास करने के लिए सभापति पर दबाव बनाते रहे। वार्ड-23 की पार्षद नेहा साहू ने आरोप लगाया कि, वार्ड-2 में 29 विकास कार्य स्वीकृति किए गए हैं। जबकि उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं स्वीकृत हुए। इस पर वार्ड-2 के पार्षद ने नेहा साहू को अनुभवहीन बता दिया। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ।निगम कमिश्नर राजीव पाण्डेय पर चुटकी उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने निगम कमिश्नर राजीव पाण्डेय पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि, निगम कमिश्नर ने तीन महीने में इतना काम करा डाला जो पिछले तीन साल में नहीं हो पाया। अब वो काम करना ही बंद कर दिए हैं। सुबह उठते हैं और अखबार में उनके एक विजिट की फोटो आ जाती है। नए कमिश्नर के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन निगम के अधिकारियों का विकास पूरा हुआ है।

इस दौरान सदन में कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि, विकास तो दूर उन्हें पार्षद मद भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। जिससे की वो वार्ड के छोटे मोटे विकास कार्य करा सकें।

जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए भर्ती हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मिशन शक्ति कार्य₹म के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु संविदा पदों की भर्ती की जा रही है। भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्य₹म अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के तहत "मिशन शक्ति" की शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनरूप जिला स्तरीय हब हेतु जिले में 07 स्वीकृत संविदा पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षणध्मूल्यांकन उपरांत पात्र-अपात्र सूची का प्रकाशन उपरांत पात्र उम्मीदवारों का वाक इंटरव्यू कौशल परीक्षा 04 अप्रैल 2025 को समय 11:00 बजे प्रातः से स्थान सेंट पैट्रिक अकेडमी स्कूल लालपुर, चौघड़ा मनेन्द्रगढ़ जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में आयोजित किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं परिचय पत्र साथ ही पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि) भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। इसके साथ ही जिले के वेबसाईट .उंदमदकतंहंती-बीपतउपतप-ींतंजचनत.बह.हवअ.पद व कार्यालय के सूचना पटल पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अजाक डीएसपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज

21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया

मीडिया ऑडीटर, दुर्ग((निप्र))। जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी विनोद मिंज के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पद्मनाभपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में कभी भी अधिकारी की गिरफ्तारी कर सकती है। पद्मनाभपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विनोद मिंज जिले के अजाक थाने में पदस्थ हैं। जिस युवती ने मामला दर्ज कराया है वो भी दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में रहती है। 21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है। उसने बताया कि डीएसपी से उसकी मुलाकात साल 2024 में हुई थी।

धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद डीएसपी ने उसे शादी के प्रपोज किया। युवती के पूछने पर उसने खुद का कुंआरा बताया था। डीएसपी की बातों में आकर युवती ने भी शादी के लिए हां कर दी। इसके बाद डीएसपी युवती को अपने साथ ले गया और उसेक साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसने कई बार शादी का झूठा भरोसा देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती जब भी डीएसपी से शादी के लिए कहती वो किसी ना किसी बहाने से उसकी बात को काट देता था। युवती को शक हुआ तो उसने उसके बारे में और पता लगाया। इस पर उसे पता लगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बाद युवती पद्मनाभपुर थाने पहुंची और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया।

युवती के साथ की मारपीट: युवती ने बताया कि जब उसे डीएसपी के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो उसके पास गई। उसने उससे झगड़ा किया कि उसने झूठ बोलकर उसकी इज्जत से खेला। इस पर डीएसपी उसे गाली देने लगा और उसके साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं उसने कहा कि वो बहुत पावरफुल है और यदि वो पुलिस में गई तो वो उसे जान से मरवा देगा।

एक अन्य डीएसपी के खिलाफ भी दर्ज हो चुका है मामला: इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के डीएसपी ने दुर्ग में एक डॉक्टर मित्र की प%ी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। डॉक्टर प%ी ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि सुकमा जुले के जगरगुंडा में पदस्थ एसडीओपी तोमेश वर्मा उसके पति का दोस्त है। साल 2020 में वो दुर्ग में प्लॉट खरीदने के सिलसिले में उनके घर आया था। इसके बाद 31 अगस्त 2024 की शाम 7.30 बजे वो फिर से उसके घर पहुंचा। उस समय घर पर अकेली थी। इस पर उसने जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

गुजरात में 10 के लिए 40 बच्चों ने हाथ काटे

अमरेली (एजेंसी)। गुजरात में एक गांव के सरकारी स्कूल में 40 बच्चों ने शार्पनर से अपने हाथ काट लिए। यह सभी 5वीं से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इन्हें स्कूल के ही 7वीं क्लास के एक बच्चे ने टास्क दिया था कि जिसके हाथ ज्यादा घाव होंगे, उसे 10 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस स्टूडेंट को वीडियो गेम में ब्लू व्हेल गेम खेलकर ऐसा टास्क देने का आइडिया आया था। पिछले 8-10 दिन से बच्चे अपने हाथ पर कट लगा रहे थे। बुधवार को एक बच्चे के हाथ में कट देखकर उसके पेरेंट्स ने स्कूल में जाकर इसकी शिकायत की, तब मामला उजागर हुआ। 10 बच्चों से शुरू हुआ खेल 40 तक पहुंचा मामला अमरेली जिले में मोटा मुंजियासर गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। स्कूल से मिली जानकारी के मुताबिक, कक्षा 7 के एक स्टूटेंट ने अपनी क्लास के अन्य स्टूडेंट्स को ब्लेड से हाथ काटने का टास्क दिया था। पहले उसकी क्लास के करीब 10 बच्चे इसमें शामिल हुए और फिर धीरे-धीरे कर पांचवीं से आठवीं क्लास तक के 40 बच्चे टास्क में शामिल हो गए। स्टूडेंट ने टास्क के दौरान शर्त रखी थी कि जिसके हाथ पर ज्यादा यह गहरे घाव होंगे, उसका ही टास्क पूरा माना जाएगा। टास्क पूरा करने वाले को 10 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो स्टूडेंट टास्क पूरा नहीं कर पाएगा तो उसे 5 रुपए देने होंगे। जांच में पता चला है कि टास्क देने वाला स्टूडेंट मोबाइल लेकर स्कूल आता है और घर पर अक्सर ऑनलाइन गेम खेलता है। अमरेली के एएसपी जयवीर गढ़वी ने स्कूल पहुंचकर अभिभावकों के बयान दर्ज किए।

तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रस्ताव के विरोध में कहा- ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिल वापस ले। स्टालिन ने कहा कि, केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ हैं। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा- संशोधन में कहा गया है कि दो गैर मुस्लिम लोग को वक्फ का हिस्सा होना चाहिए। मुसलमानों को डर है कि यह सरकार का वक्फ संपत्तियों को हड़पने का एक तरीका है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राज्य सरकार के विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाने पर भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने कहा- भाजपा इस प्रस्ताव का विरोध करती है। केंद्र सरकार के पास संशोधन लाने का अधिकार है। वक्फ से जुड़ी कई शिकायतें थीं, जिसके बाद इसमें केंद्र सरकार संशोधन कर रही है।

कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या की जमानत अर्जी खारिज

बेंगलुरु (एजेंसी)। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका गुरुवार को बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। यह तीसरी बार है, जब कोर्ट ने रान्या को जमानत देने से इनकार किया है। इससे पहले 12 और 14 मार्च को दो बार कोर्ट ने रान्या को जमानत नहीं दी थी। उधर, मामले में 26 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय ने बेल्लारी से सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को अरेस्ट किया।

स्पेस पॉलिसी के निर्माण और प्रदेश में इसरो के केंद्र के लिए होंगे प्रयास-मुख्यमंत्री

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझाने की क्षमता विज्ञान में हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से अनेक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। फार्मिंग से लेकर फायनेंस तक मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक और एजुकेशन से लेकर कम्यूनिकेशन तक प्रत्येक क्षेत्र का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत एक दशक में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राष्ट्र में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विजनरी नीति का ही परिणाम है कि भारत डिफेंस और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत इस क्षेत्र में गलोबल लीडर बन रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाई जाएगी। प्रदेश में इसरो के केंद्र की शुरूआत के लिए भी मंथन प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जीआईएस के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित 4 नीतियों को लागू करने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को उज्जैन में हो रहे राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन/ विज्ञान उत्सव और चालीसवें मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअल रूप से शुभारंभ करते हुए यह बात कही। यह सम्मेलन कालिदास अकादमी परिसर उज्जैन में हो रहा है। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम टेटवाल भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए।

लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा।% उन्होंने कहा, %मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। जो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं। कहां रुक रहे हैं। क्या कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था। इस पर सत्ता और विपक्ष के 30 सांसदों ने अपनी बात रखी।

नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे= हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान हैं, सेना के अड्डे हैं, उनको दुनियाभर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते थे। पहले भी घुसपैठियों को रोका जाता था, लेकिन तब इसका नियम नहीं था। हममें हिम्मत है नियम बनाकर रोकने की। पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम किया गया है।भारत आए विदेशियों की जानकारी पुख्ता होगी= सुरक्षा की दृष्टि से ड्रग्स कार्टल, घुसपैठियों की कार्टल, हवाला व्यापारियों को समाप्त करने की व्यवस्था हम इस बिल में कर रहे हैं। पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य होगा। विदेशियों के रजिस्ट्रेशन को और पुख्ता किया जाएगा।पहले ये कानून ब्रिटेन में बने थे अब नई संसद में= अप्रवासियों से जुड़े कानून 1920, 1930 और 1946, ब्रिटेन की संसद में बने थे। भारत का कानून अब भारत की नई संसद में बन रहा। राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी ध्वनि मत से पारित किया गया।राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी ध्वनि मत से पारित किया गया।विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए चौकियां बढ़ाई= विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए हमने 73ब अप्रवासन चौकियां बढ़ाई हैं।

जज कैश केस, 6 बार एसोसिएशन पदाधिकारी सीजेआई से मिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। 6 हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी गुरुवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मिले और तबादला पर विचार करने की मांग की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना से हम लोगों ने मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस वर्मा के तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लेने की मांग पर विचार करेंगे।

सदस्यों ने सीजेआई और कॉलेजियम को एक मेमोरेंडम दिया। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। इसके एक दिन बाद किसी ने उनके घर से सामान हटा दिया था।

चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। केदारनाथ-बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। समुद्र तल से 12 हजार फीट ऊपर केदारनाथ धाम में ढोल नगाड़ों का शोर सिर्फ रील बनाने के लिए किया गया था। यात्रा शुरू होने के बाद 10 से 12 दिन तक पूरी शिवालिक पर्वतमाला में यह शोर गूंजता रहा। यहां की प्रकृति के लिए यह शोर ठीक नहीं है। इसलिए इस बार कैमरा ऑन भी नहीं करने देंगे। इसी तरह, पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था भी धामों पर बंद रहेगी। बद्रीनाथ धाम

के पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया ने कहा है कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है।

इस साल 30 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। इसी दिन सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

फोटो सेशन के दौरान नीतीश ने जोड़े हाथ,मंत्री ने हटाया

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को विधान परिषद के सदस्यों का फोटो सेशन हुआ। इस दौरान सभी एमएलसी ने सीएम नीतीश के साथ फोटो खिंचवाई। फोटो सेशन के दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों का अभिवादन कर हाथ जोड़ रहे थे। फोटोग्राफर उन्हें हाथ नीचे करने के लिए कह रहे थे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार ने बिजेंद्र यादव की ओर देखा फिर मुस्कुराने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मिनट तक बेवजह हाथ जोड़े बैठे रहे, भूल गए कि हाथ अब नीचे भी करने हैं। खिसिया कर तैश में आकर उनके मंत्री ने ष्टरूके जुड़े हाथों पर झटके से अपना हाथ मारा और ष्टरूके हाथ नीचे किए या गिराए। अब क्या ही कहा जाए? कभी अधिकारी उनके हाथ नीचे करते हैं तो कभी मंत्री तो कभी संतरी। क्या अब कुछ और देखना या सुनना बाकी रह गया है। अब नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य के कारण उनका महत्व एक मुखोटे से अधिक का नहीं रह गया है।

जम्मू के कठुआ में सेना-आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में गुरुवार की सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। डीएसपी धीरज सिंह समेत चार पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। जुठाना इलाके में 4-5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले सोमवार को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच

मुठभेड़ हुई थी। तब आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता-पिता को पकड़ लिया था।

मौका मिलने पर तीनों आतंकियों के चंगुल से भाग निकले थे। इस दौरान बच्ची की मामूली चोटें आई थीं। आतंकी भी भाग निकले थे। 1 हफ्ते पहले कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, एक जवान घायल कुपवाड़ा जिले में 17 मार्च को एलओसी से सटे खुरमोरा राजवार इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक आतंकी मारा गया, जबकि कुछ आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहे थे। मुठभेड़ में एक सैनिक भी घायल हुआ था। अधिकारियों ने बताया था कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जचलदारा के क्रुम्हूरा गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों के सुरक्षाबलों पर गोलीबारी के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुबह से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। उसके पास एक असॉल्ट राइफल भी मिली थी।

शिक्षा के भविष्य पर चर्चा हुई, शिवराज बोले- शिक्षा का मकसद ज्ञान, कौशल और संस्कार देना है

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में दैनिक भास्कर एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ। इसमें देशभर से 200 से ज्यादा शिक्षाविद शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा नीति, ब्रांडिंग, फंडिंग और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। शिक्षित भारत, विकसित भारत% विषय पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह केवल पीढ़ियों के अर्जित ज्ञान को स्थानांतरित करने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करने का जरिया भी है। वहीं, राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को हर स्तर पर सुलभ बनाना है, ताकि हर नागरिक अपने सपनों को साकार कर सके और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके।

प्रोग्राम में नई शिक्षा नीति को लेकर भी चर्चा हुई कॉन्क्लेव के दौरान विजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विषय पर (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के अध्यक्ष टी.जी. सीताराम ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली में तकनीक, नवाचार और उद्योग से जुड़ाव को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर गुरुवार को पुलिस ने लाठियां बरसाईं और वाटर कैनन चलाई। दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। कांग्रेस 14 विधायक के निलंबन का विरोध कर रही थी।

दरअसल 25 मार्च को कांग्रेस के 12 विधायक निलंबित कर दिए गए थे। इसके बावजूद विधायक प्रदर्शन करते रहे और पूरी रात सदन में बिताई। विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। अगले दिन यानी 26 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता और निलंबित विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते रहे। वे विधानसभा की बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद जमकर धक्का-मुक्की हुई।

सदन के भीतर कांग्रेस के बचे हुए दो विधायकों तारा प्रसाद बाहिनीपति और रमेश जेना ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। दोनों सदन की वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे इसलिए उन्हें भी

निलंबित कर दिया गया था। पुलिस की 80 प्लाटून तैनात न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जगमोहन मीना ने बताया- विधानसभा की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस की 80 प्लाटून तैनात की गई हैं। इनमें 10 प्लाटून महिला कर्मियों की हैं। ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स की भी तैनाती की जा रही है। इसका इस्तेमाल दंगों से निपटने के लिए किया जाता है। अनुशासनहीनता के चलते हुआ निलंबन कांग्रेस विधायक भाजपा सरकार के आठ महीनों के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने नारेबाजी की और नारे लिखी तख्तियां लेकर वेल में प्रदर्शन किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता और सदन की गरिमा भंग करने के आरोप में सात दिन के लिए निलंबित कर दिया

लखनऊ में आश्रय केंद्र के 4 बच्चों की मौत

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में निर्वाण आश्रय केंद्र में 4 बच्चों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चियां हैं। यहां के 35 बच्चों को उल्टी-दस्त होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 20 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। बच्चों के बीमार होने की शुरुआती वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। उनको उल्टियां हो रही हैं, जिसमें 6 इंच तक के कीड़े भी निकले। इन कीड़ों के दिमाग तक पहुंचने का डर है। लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजीव दीक्षित ने बताया- बच्चों में पानी की कमी थी। सभी में डायरिया के लक्षण मिले हैं।

इस घटना का पता चलते ही बुधवार रात 8 बजे डीएम विशाख जी लोकबंधु अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, गुरुवार सुबह 9 बजे कमिश्नर रोशन जैकब, प्रमुख सचिव लीना जौहरी और एक बार फिर डीएम लोकबंधु हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चों से बातचीत की। कहा, आश्रय केंद्र के पानी की जांच कराई जाएगी।

आश्रय केंद्र, लोकबंधु अस्पताल और जिला प्रशासन ने इस घटना को 3 दिन तक छिपाए रखा। एक के बाद चार मौतें हुईं, लेकिन आलाधिकारियों को गुमराह किया गया। यह मामला तब खुलकर सामने आया, जब केजीएमयू में भर्ती एक बच्चे की मौत हो गई।

निर्वाण आश्रय केंद्र पारा इलाके के बुद्धेश्वर में बना है। यह सरकार की मदद से पीपीपी मॉडल पर संचालित होता है। मानसिक कमजोर, अनाथ और लावारिस बच्चों को यहां रखा जाता है। अभी यहां 146 बच्चे हैं। ज्यादातर की उम्र 10 से 18 साल के बीच है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा- अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है। कुछ को छुट्टी भी दे दी गई है। हम खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

विनेश फोगाट के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान,सिल्वर मेडलिस्ट जैसा होगा सम्मान

नई दिल्ली (एजेंसी)। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वह वादा पूरा किया जो उन्होंने पेरिस ओलंपिक के दौरान किया था। ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश करने पर नायब सैनी ने कहा था कि किसी भी कारण से विनेश ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाए हो लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा। विनेश फोगाट ने कुल दिन पहले विधानसभा में नायब सैनी को उनका ये वादा याद दिलाया था जिसके बाद ये ऐलान किया था। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी लेकिन वह डिस्क्वालिफाई हो गई थीं। हालांकि, नायब सैनी ने तब ऐलान किया था कि वह विनेश को भी वही सम्मान और अवॉर्ड देंगे जो कि देश के सिल्वर मेडलिस्ट को मिलता है। कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि पेरिस ओलंपिक को आठ महीने बीतने के बावजूद उन्हें पुरस्कार राशि नहीं मिली है। हरियाणा सरकार की सिल्वर मेडल की नीति के तहत 3 तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें नकद पुरस्कार के रूप में 4 करोड़ रुपये, ग्रुप ए ओएसपी नौकरी, एचएसवीपी का प्लाट शामिल होता है। खिलाड़ी किसी एक चीज को चुन सकते हैं।

इंपैक्ट प्लेयर नियम को अब टी20 क्रिकेट के विकास का हिस्सा मान रहे धोनी

मुम्बई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बहस जारी है। जहां स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इसे सही नहीं मानते। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मेहेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि जब इस नियम को पहली बार लागू किया गया तो वह इसकी जरूरत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे पर अब उन्हें लगता है कि ये टी20 क्रिकेट के विकास का ही एक हिस्सा है। धोनी हालांकि अपने को इंपैक्ट प्लेयर नहीं मानते हैं। इसका कारण है कि वह अभी भी विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। धोनी ने कहा, 'जब पहली बार यह नियम लागू किया गया तो मुझे लगा कि वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है हालांकि कुछ हद तक ये उनके लिए फायदेमंद रहा भी और नहीं भी। साथ ही कहा कि मैं अभी विकेटकीपिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं इंपैक्ट प्लेयर नहीं हूं। मुझे इसके अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। कई लोगों का कहना है कि इस नियम के कारण बड़े स्कोर बन रहे हैं पर मेरा मानना है कि खिलाड़ियों के सहज होकर खेलने से ऐसा हो रहा है क्योंकि अब उनके ऊपर दबाव नहीं है। वहीं रोहित और पांड्या जैसे खिलाड़ियों का मानना है कि इस नियम से ऑल राउंडरों को नुकसान हो रहा है। टीम इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका के लिए आक्रामक बल्लेबाजों को ही शामिल कर रही है। धोनी ने कहा कि इस नियम से टीमों को कड़ी हालातों में एक अतिरिक्त बल्लेबाज रखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि एक अतिरिक्त बल्लेबाज रखने के कारण ही बड़े स्कोर बन रहे हैं।

बीसीसीआई केन्द्रीय अनुबंध में रोहित सहित इन तीन दिग्गजों को हो सकता है नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) आने वाले दिनों में केन्द्रीय अनुबंध की घोषणा कर सकता है। इसमें श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल , यशस्वी जायसवाल सहित कुछ खिलाड़ियों को लाभ हो सकता है जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को नुकसान को सकता है। ये तीनो ही अभी ए प्लस वर्ग में हैं जिसमें तीनों प्रारुप खेलने वाले खिलाड़ी ही रह सकते हैं। इन तीनों ने ही टी20 प्रारुप से संन्यास ले लिया है। ऐस में इन तीनों को इस प्रारुप से बाहर किया जा सकता है। ए प्लस वर्ग में 7 करोड़ रुपये की रिटेनरशिप फीस मिलती है। वहीं ए वर्ग में खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं जबकि ग्रेड-बी और सी में खिलाड़ियों को 3 करोड़ और 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। केन्द्रीय अनुबंध राष्ट्रीय चयन समिति बनाती है। पिछले साल बुमराह, रोहित, कोहली और जडेजा को ए प्लस में रखा गया था। अब केवल बुमराह ही ऐसे हैं जो तीनों प्रारुपों में खेलते हैं। वह टेस्ट के कप्तान भी बन सकते हैं। ऐसे में इस वर्ग में तीनो प्रारुपों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है। वहीं ए वर्ग से आर अश्विन बाहर होंगे क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है।

ऋषभ के बचाव में उतरे गावसकर

मुम्बई (एजेंसी)। आईपीएल के पहले ही मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद जहां लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के नये कप्तान ऋषभ पंत आलोचकों के निशाने पर है। वहीं भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उनका समर्थन किया है। गावस्कर ने ऋषभ को एक समझदार क्रिकेटर कहा है। गावस्कर ने कहा कि केवल एक मैच से ही ऋषभ की कप्तानी का आंकलन न करें। अभी 13 मैच बचे हैं। उन्हें लगता है कि इस क्रिकेटर के पास अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के बारे में काफी मूल्यवान जानकारी होगी और जिसे वह आने वाले मैचों में अपने प्रदर्शन से साबित करेंगे।

इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, मुझे लगता है कि वह जानता है। उसने मैच के बाद भी कहा कि कि आप अपनी सफलताओं की तुलना में अपनी गलतियों से अधिक सीखते हैं। गावस्कर ने कहा, जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप बल्ले या गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों को समझने की जरूरत होती है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। यह सिर्फ पहला मैच है, और अभी 13 और मैच होने हैं। ऋषभ एक बुद्धिमान क्रिकेटर हैं, और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के बारे में जरुरी जानकारी हासिल की होगी। मुझे विश्वास है कि हम उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करते देखेंगे। इसके अलावा जब कोई कप्तान रन बनाता है या विकेट लेता है, तो इससे गेंदबाजी में बदलाव करने और फील्ड जमाने में उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। एक बार जब वह कुछ रन बना लेता है, तो मुझे उम्मीद है कि उसकी कप्तानी और भी बेहतर हो जाएगी।

लखनऊ के कप्तानी संभालते ही ऋषभ पहले मैच में अच्छे स्कोर के बाद भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाये। उनके गेंदबाज 210 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाये। दिल्ली कैपिटल्स ने अंत में आशुतोष शर्मा की आक्रामक पारी से मैच अपने कब्जे में कर लिया। इस मैच में अंतिम ओवरों को स्पिनरों को दिये जाने के ऋषभ के फैसलों को भी गलत माना जा रहा है।

कप्तानी मिली तो संभालने तैयार हूं - रबाडा

मुम्बई (एजेंसी)। भारत में आईपीएल खेल रहे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने कहा है कि अगर अब भी उन्हें क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) कप्तान बनाता है तो वह ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। वह एक साथ कई भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हैं। रबाडा ने एक साक्षात्कार में कहा, 'मुझसे कई बार कप्तानी को लेकर सवाल पूछा गया है। इससे इसने मुझे इस पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। मुझे लगता है कि इसके लिए मेरी ओर से कुछ परिपक्वता की आवश्यकता होगी पर अगर क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका या किसी कोच द्वारा मुझसे यह सवाल पूछा जाता है तो मैं था कि इसमें किस तरह का बदलाव होगा क्योंकि कप्तान बनने के बाद आप केवल अपने आप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि तब आपको हर किसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

अभिषेक शर्मा टी20 फॉर्म के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एसआरएच के पूर्व कप्तान ने किया हैरान करने वाला खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 में अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे इस टीम ने आईपीएल के 18वें सीजन के लिए रिटेन किया था। अभिषेक शर्मा टी20 प्रारूप के बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं और इसकी क्या वजह से इसके बारे में हैदराबाद के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने बताया।

केन विलियमसन के मुताबिक अभिषेक शर्मा के पास आखिरी समय में शॉट्स बदलने और मैदान के चारों तरफ पूरी ताकत के साथ शॉट मारने की जबरदस्त क्षमता है। केन ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा कि उनके पास बेहतरीन बैट स्विंग है और वो गेंद को नैचुरल तरीके से समय पर खेलते हैं। उनके पास ताकत का उपहार है और वो गेंद को जबरदस्ती अपनी ताकत से नहीं खेलते हैं। केन ने कहा कि उनके पास गेंद को टाइम करने और मैदान के चारों तरफ खेलने की जो क्षमता है जो सही मायने में सुपर पावर की तरह से है। वो काफी हद तक हेनरिक क्लासेन की तरह से हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आखिरी मिनट में अपने शॉट को बदल देते हैं क्योंकि वो ओवरहिटिंग नहीं करते हैं और सच कहें तो ये एक ऐसा स्किल है जो बहुत सारे बैट्समैन के पास नहीं है।

केन विलियमसन ने कहा कि जब हैदराबाद ने उन्हें आईपीएल 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स से खरीदा था तब से ही लगा था कि उनमें गजब की प्रतिभा है, भले ही उन्होंने इससे पहले सिर्फ 3 मैच आईपीएल में खेले थे।

मुझे ये भी पता था कि कुछ खिलाड़ी युवराज सिंह के मार्ग दर्शन में खेल रहे थे और अभिषेक व शुभमन गिल उनमें से एक थे तो जाहिर है कि युवी की देखरेख में खेलने वाले खिलाड़ी प्रतिभाशाली जरूर होंगे।

दिल्ली कैपिटल्स से ये खिलाड़ी होगा बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली कैपिटल्स ने पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रोमांचक अंदाज में जीता था। अब इस जीत के बाद टीम को एक और खुशखबरी मिली है। दरअसल, रविवार को होने वाले दिल्ली के अगले मुकाबले में केएल राहुल खेलेंगे। बता दें कि, केएल राहुल पत्नी आथिया शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया है और केएल राहुल ने पहला मैच नहीं खेला था। राहुल अपनी पत्नी के साथ मुंबई के अस्पताल में थे। लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि राहुल रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में खेलेंगे। अब केएल राहुल के खेलने का मतलब है कि एक खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर होना होगा। केएल राहुल के टीम में आने का मतलब ये है कि दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन से एक बल्लेबाज की छुट्टी होगी। तलवार समीर रिज्वी पर लटक रही है जो पिछले मैच में नंबर 4 पर खेले थे। बताया जा रहा है कि केएल राहुल भी नंबर 4 पर खेल सकते हैं। वैसे केएल राहुल विकेटकीपिंग करेंगे तो अभिषेक पोरेल का पत्ता भी साफ हो सकता है। आईपीएल की बात करें तो केएल राहुल का प्रदर्शन बेहद कमाल का है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 123 आईपीएल पारियों में 45 से ज्यादा की औसत से 4683 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने आईपीएल में 37 अर्धशतक और 4 शतक भी जड़े हैं। केएल राहुल पिछले सीजन तक लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे लेकिन इस बार उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। ये खिलाड़ी 14 करोड़ की बड़ी कीमत पर बिका। केएल राहुल कप्तान बनने के दावेदार थे लेकिन उन्होंने खुद ही दिल्ली का कप्तान बनने से मना कर दिया। इसके बाद अक्षर पटेल को टीम की कमान मिली। राहुल का ये फैसला उनके खुद के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये खिलाड़ी अब सिर्फ बल्लेबाज पर ध्यान लगा सकता है। राहुल ने चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल की बैटिंग कर टीम को चैंपियन बनाया है, दिल्ली को भी उनसे यही उम्मीद रहेगी।

लियोनल मेसी के साथ अर्जेंटीना फुटबॉल टीम इस साल भारत आएगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। दरअसल, दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलरों में शुमार लियोनल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ भारत आएंगे। अर्जेंटीन टीम इसी साल में मैच खेलने आएगी। बता दें कि, मेसी इससे पहले 2011 में आखिरी बार भारत आए थे, अब 14 साल बाद फुटबॉल स्टार वापस भारत आ रहे हैं। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम अक्टूबर 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मैच केलिए भारत का दौरा करेगी। इस टीम में स्टार प्लेयर लियोनल मेसी भी शामिल होंगे। करार के तहत अर्जेंटीन टीम भारत के केरल में इसी साल अक्टूबर में एक फ्रेंडली मैच खेलने आएगी। ये मैच केरल के कोच्चि में खेला जाएगा। एएफए के अध्यक्ष क्लाउडियो फैबियन तापिया ने इस करार को टीम के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में एक नया मील का पत्थर बताया है। बता दें कि, इससे पहले लियोनल मेसी आखिरी बार सितंबर 2011

में भारत दौरे पर आए थे। उस समय अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला टीम के खिलाफ मैच खेला था। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में अर्जेंटीना ने 1-0 से जीत हासिल की थी।

कर्ज में डूबा पाकिस्तान.. अब दुनियाभर में हो रही फजीहत, इस बड़े टूर्नामेंट से हो गया बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगने की कगार पर आ गया है। वहीं आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज के कारण पाकिस्तान को हमेशा दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। पाकिस्तान का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, पिछले साल कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान पर 271.2 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। अब पाकिस्तान से एक और ऐसी ही खबर सामने आई है, जिससे दुनिया के सामने उसकी एक बार फिर बेइज्जती हो रही है। दरअसल, मलेशियाई हॉक महासंघ ने बकाया कर्ज के कारण इस साल होने वाले अजलन शाह कप के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित ही नहीं किया है।

पाकिस्तान हॉकी टीम पिछले साल हुए इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचा था। जहां वह हार गया था। पिछले साल की उपविजेता टीम को इस बार बकाया कर्ज के कारण टूर्नामेंट से बुलावा ही नहीं आया। पाकिस्तान हॉकी महासंघ के एक सूत्र के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक पूर्व अधिकारी ने अजलन शाह कप के पिछले सीजन के दौरान कुछ गलत फैसले लिए थे, जिससे पीएचएफ एमएचएफ यानी मलेशियाई हॉकी महासंघ के कर्ज में डूब गया। मलेशियाई संघ के आयोजक इससे खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने पिछले साल के उपविजेता पाकिस्तान को आगामी टूर्नामेंट के लिए बुलावा ही नहीं भेजा।

सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अधिकारी एमएचएफ के साथ इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये मामला सुलझा लिया जाएगा और इस हफ्ते के अंत में उन्हें भी आमंत्रण मिल जाएगा।

मार्कस स्टोइनिस हुए भारतीय युवा खिलाड़ियों से प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर और आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे मार्कस स्टोइनिस भारतीय युवा खिलाड़ियों के बेखौफ होकर खेलने से काफी प्रभावित हैं।

बता दें कि, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारुप से संन्यास लेने के बाद तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने आईपीएल में अपने पहले ही मैच में आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हुए सभी को प्रभावित किया।

स्टोनइनिस ने पीटीआई से कहा कि, भारतीय क्रिकेट में काफी गहराई है। वह हमेशा से रही है। मेरा मानना है कि उनके खिलाड़ियों का विश्व स्तर पर अपने कौशल का

नमूना पेश करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि, वे आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं। उन्हें अपने करियर के शुरू से ही आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में दबाव की परिस्थितियों से गुजरने का फायदा मिल रहा है। खेल के प्रति उनका बेखौफ अंदाज वास्तव में बेहतरीन है। उन्होंने आगे कहा कि, पंजाब किंग्स की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो इससे पहले कभी आईपीएल में नहींखेले थे लेकिन वह बेहद प्रभावशाली हैं।

पंजाब ने आईपीएल के 18वें सीजन में अपना पहला मैच गुजरात टाइटंस के खिलाप खेला और 11 रनों से रोमांचक जीत भी हासिल की। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पंजाब के लिए अपने पहले मैच में 42 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 9 छक्के और 5 चौके जमाए। पंजाब ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 का स्कोर बनाने के बाद जीटी को पांच विकेट पर 232 रन पर ही रोक दिया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने वेसिक्स आफ क्रिटिकल केयर इन आब्सटेटरीज विषय पर आयोजित कार्यशाला का किया शुभारंभ

मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये समन्वित प्रयास आवश्यक

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये समन्वित प्रयास आवश्यक है। मातृ मृत्युदर को कम करने में चुनौती के साथ संभावनाएँ हैं। गर्भवती महिला की समय-समय पर जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श देकर एवं उनके परिजनों को जागरूक कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में गायनी विभाग के तत्वाधान में वेसिक्स ऑफ क्रिटिकल केयर इन आब्सटेटरीज विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन हो। उसकी समय-समय पर जांच की जाकर चिकित्सकीय परामर्श दिया जाय और यह प्रयास हों कि वह क्रिटिकल अवस्था में पहुंचे ही नहीं। चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ देकर एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता व स्टाफ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए गर्भवती महिला का ध्यान रखें और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने का समन्वित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की गई है। मेडिकल कालेज खोले गये हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों को सुविधायुक्त बनाया जा रहा है ताकि वहां जिला अस्पताल जैसी सभी सुविधाएँ मुहैया रहें। उन्होंने चिकित्सकों व स्वास्थ्य विभाग के अमले को इस चुनौती का सामना करते हुए संकल्प शक्ति के साथ कार्य करने की अपेक्षा की ताकि हमारा प्रदेश मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर कम कर पाने में सफल हो सके। शुक्ल ने कहा कि कार्यशाला में विचार विमर्श व प्राप्त सुझावों का नीचे स्तर तक लाभ मिलेगा और यह कार्यशाला सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कार्यशाला में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ व बीएमओ की उपस्थिति की बात कही। कार्यशाला को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने भोपाल से वीडियो कांफ्रेंसिग से सम्बोधित किया। इस अवसर पर डायरेक्टर एनएचएमएमसीएच (रेगुलेशन एण्ड पॉलिशी) डॉ. अरूणा कुमार ने पीपीटी के माध्यम से मातृ मृत्यु दर का संभागवार प्रस्तुतीकरण देते हुए उसे कम करने के विषय में जानकारी दी। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरूण वास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि कार्यशाला से चिकित्सक सीख लेकर समर्पण भाव से कार्य करें तो हम प्रदेश में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम कर सकेंगे। उन्होंने शोध व अकादमिक स्तर को सशक्त बनाने की भी बात कही। अरूण वास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पर्याप्त बजट प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। रीवा भी उक्त स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदेश में पीछे नहीं है।

इससे पूर्व कार्यशाला के उद्देश्य से जानकारी देते हुए डॉ. बीनू कुशवाहा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉ. राहुल मिश्रा सहित प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय के गायनी विभाग के चिकित्सक, मेडिकल कालेज के चिकित्सक तथा छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

जल गंगा संवर्धन अभियान को जन-जन का अभियान बनाएं - कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि 30 मार्च से 30 जून तक जिले भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। सभी संबंधित विभाग दो दिवस में अभियान की कार्ययोजना बनाकर जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं। पानी जीवन का आधार है। पानी का विवेकपूर्वक उपयोग और वर्षा जल का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामाजिक संगठनों को भी सहभागी बनाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान को जन-जन का अभियान बनाएं।

कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम अपने अनुभाग में अभियान का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के इस अभियान की तैयारी के लिए क्लस्टर लेबल पर बैठक आयोजित कर प्रत्येक गांव के लिए जल संरक्षण की कार्ययोजना तैयार कराएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण का कम से कम एक कार्य अनिवार्य रूप से कराएं। सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में 30 मार्च को समारोह पूर्वक अभियान का शुभारंभ करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमृत सरोवर, खेत तालाब निर्माण, हैण्डपंपों में सोकपिट बनाने तथा पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य अभियान के दौरान कराएं। अभियान की प्रत्येक गतिविधि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जल संरक्षण कार्यों, श्रमदान, जल संवाद तथा जन जागरूकता के कार्यक्रमों के अच्छे फोटोग्राफ्स और वीडियो जनसम्पर्क विभाग को उपलब्ध कराएं। साथ ही अभियान की वेबसाइट में अपलोड करें।

कलेक्टर ने कहा कि कार्यपालन यंत्री पीएचई अभियान के दौरान नलजल योजनाओं की पाइपलाइन में सुधार तथा सभी हैण्डपंपों में सोकपिट बनाने का कार्य ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय निकायों के सहयोग से कराएं। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभी नहरों को खसरे में दर्ज कराएं। नहरों की साफ-सफाई तथा सुधार के कार्य भी अभियान के दौरान करें। जिला शिक्षा अधिकारी नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर स्कूलों में जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता के लिए निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित कराएं। साथ ही पानी की टंकियों की साफ-सफाई भी कराएं। क्षेत्रीय संचालक औद्योगिक विकास निगम चोरहटा औद्योगिक केन्द्र में औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले पानी का ट्रीटमेंट कराकर उसे शुद्ध करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कराएं। आयुक्त नगर निगम शहर के सभी हैण्डपंपों में स्थान उपलब्ध होने पर सोकपिट का निर्माण कराएं। शहर में निर्माणाधीन तीन एसटीपी का निर्माण कार्य एक माह में पूरा कराकर सभी आसपास के नालों का पानी इनसे उपचारित कराएं। अभियान के दौरान नगर निगम तथा सभी नगरीय निकायों में भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करें।

कलेक्टर ने कहा कि वन मण्डलाधिकारी वृक्षारोपण के साथ-साथ वन क्षेत्र के नालों में नाला बंधान, चेकडैम, स्टॉपडैम तथा छोटे तालाबों का निर्माण कराएं। संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद जल संवाद के आयोजन के साथ जल संरक्षण के लिए श्रमदान कराएं। साथ ही जिले की एक नदी में सफाई का अभियान चलाएं। उप संचालक कृषि और उद्यानिकी जिले भर में किसान संगोष्ठी आयोजित कर किसानों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें। किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने जल गंगा संवर्धन अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण का कम से कम एक कार्य अनिवार्य रूप से होगा। अभियान के दौरान एक 1472 खेत तालाब तथा 27 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाएगा। जल संरक्षण के सभी कार्यों की पूरी जानकारी पोर्टल पर आनलाइन दर्ज की जाएगी। सभी अधिकारी जल संरक्षण की कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह कार्यों का विवरण जिला पंचायत को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट, एसडीएम गुढ़ अनुराग तिवारी, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, एसडीएम त्योंथर संजय जैन, एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा, परियोजना अधिकारी मनरेगा शिव सोनी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

समाधान ऑनलाइन आज शाम 4 बजे से

रीवा. समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 28 मार्च को शाम 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों, डूबने की दुर्घटनाओं के प्रबंध, कानून व्यवस्थाओं की स्थिति तथा राजस्व के विषय पर भी चर्चा की जायेगी। सभी संबंधित अधिकारियों से केन्द्र में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

मऊगंज जिले में एक अप्रैल से आरंभ होगा नया शिक्षा सत्र

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मऊगंज जिले में आगामी एक अप्रैल से स्कूल शिक्षा विभाग का वर्ष 2025-26 का नया शिक्षा सत्र आरंभ हो रहा है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने शासकीय स्कूलों में नवीन शिक्षा सत्र के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक शिक्षा मिशन को नवीन शिक्षा सत्र के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का शाला में अनिवार्य रूप से प्रवेश कराएं। अब तक कक्षा दो से लेकर कक्षा 11 तक जो विद्यार्थी दर्ज हैं उनका पूरा विवरण समग्र शिक्षा पोर्टल पर 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपडेट कराएं। विकासखण्ड स्तर पर विद्यार्थियों एवं पालकों के साथ बैठक आयोजित करके एक अप्रैल से नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने की जानकारी दें। स्थानीय संचार माध्यमों से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का शाला में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजनता का भी पूरा सहयोग लें।

कलेक्टर ने कहा है कि शाला प्रबंधन समिति एवं पालकों की बैठक आयोजित करें। विद्यार्थी के अभिभावक से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में उपयोगी सुझाव प्राप्त करें। अभिभावकों को विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति से भी अवगत कराएं। सभी शालाओं में एक अप्रैल को समारोह पूर्वक प्रवेश उत्सव का आयोजन करें। इस दिन विद्यार्थियों का परंपरागत तरीके से स्वागत करने के साथ प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में विशेष मध्यान्ह भोजन का भी आयोजन करें। प्राथमिक शाला के शिक्षक आंगनवाड़ी केन्द्र जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कक्षा एक में प्रवेश योग्य बच्चों की सूची प्राप्त करें। उनके अभिभावकों से संपर्क करके बच्चों का शाला में प्रवेश सुनिश्चित करें। बच्चे के कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु संबंधी प्रमाणीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, एएनएम के रजिस्टर तथा आंगनवाड़ी केन्द्र के रजिस्टर को भी आधार बनाएं।

श्रमिकों को संबल दे रही मध्यप्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

द्वारा

23 हजार 162 परिवारों को

₹ 505 करोड़ की अनुग्रह राशि का

अंतरण

28 मार्च, 2025 | दोपहर 2:30 बजे
मंत्रालय, भोपाल

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

संबल योजना में

गिग वर्कर्स भी शामिल

- संबल योजना में 1 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रमिक भाई-बहन पंजीयन करा चुके हैं।
- अब तक कुल 6 लाख 58 हजार से अधिक प्रकरणों में राशि ₹5927 करोड़ से अधिक का हितलाभ वितरण किया गया है।
- पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख की अनुग्रह सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक की स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख, आंशिक स्थाई अपंगता पर ₹1 लाख की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ₹5 हजार की अंत्येष्टी सहायता।
- सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम् योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है।
- संबल हितग्राहियों को रियायती दरों पर राशन की सुविधा।
- संबल हितग्राहियों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत महाविद्यालय (मेडिकल, विधि, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक आदि) में शिक्षा हेतु सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- पंजीकृत महिला श्रमिक व पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल ₹16 हजार की राशि की सहायता।

D11216/24 सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।